हिन्दी दैनिक

पथ प्रवाह

RNI No.: UTTHIN/2011/39282

हर खबर पर पैनी नजर

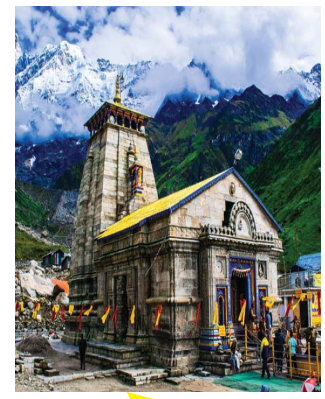

वर्ष:5 अंक:24 पृष्ठ:08 मुल्य:1 रूपये | pathpravah.com | हरिद्वार, गुरूवार, 29 जनवरी 2026

अजित पवार का प्लेन क्रॅश में निधन

मुंबई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया है। बुधवार सुबह 8.45 बजे बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया। वे 66 साल के थे। हादसे में पवार के सुरक्षाकर्मी, दो पायलट और एक महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की जान गई। पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करने बारामती जा रहे थे। वे मुंबई से सुबह 8.10 बजे रवाना हुए थे। महाराष्ट्र एविएशन डिपार्टमेंट के मुताबिक पायलट ने सुबह 8.45 बजे बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश की थी, लेकिन रनवे साफ दिखाई नहीं दिया तो वह विमान को दोबारा ऊंचाई पर ले गया। पहली कोशिश नाकाम रहने के बाद बारामती के रनवे-11 पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश की गई। इस दौरान विमान रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया। इसके तुरंत बाद उसमें आग लग गई। जानकारी मिली है कि लैंडिंग के दौरान पायलट ने कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं दिया था। उसने मेडे कॉल भी नहीं किया था।

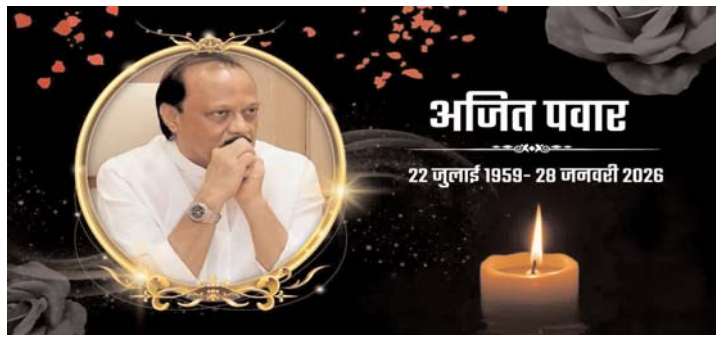

महाराष्ट्र में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। पवार का अंतिम संस्कार बारामती में गुरुवार सुबह 11 बजे किया जाएगा। अजित के चाचा शरद पवार, पत्नी सुनेत्रा, दोनों बेटे और बहन सुप्रिया सुले भी बारामती पहुंच गई हैं।

डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजित पवार की विमान हादसे में मौत के बाद देशभर में शोक की लहर है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हादसे की जांच की मांग की है। उन्होंने एक्स पर शोक संदेश में अजित पवार के असामयिक निधन पर शोक जताते हुए प्लेन क्रैश में साजिश की आशंका जाहिर की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस हादसे की जांच की मांग की। ममता बनर्जी ने इशारा किया कि इस घटना में साजिश हो सकती है क्योंकि अजित पवार महायुति गठबंधन से दूरी बना रहे थे। उन्होंने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पंवार के निधन पर जताया शोक

पथ प्रवाह, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान दुर्घटना में निधन पर दुःख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हृदयविदारक घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि अजीत पवार ने समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के कल्याण के लिए सदैव करुणा, संवेदनशीलता एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि इस दुःखद हादसे में दिवंगत सभी पुण्यात्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोकाकुल परिजनों, सहयोगियों एवं समर्थकों को यह असह्य दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित उत्तराखंड की कैबिनेट ने भी विमान दुर्घटना में दिवंगत आत्माओं की शांति हेतु दो मिनट का मौन रखा गया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1035 सहायक अध्यापकों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र

पथ प्रवाह, देहरादून

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, पटेलनगर, देहरादून में 1035 सहायक अध्यापक (प्राथमिक शिक्षा) को नियुक्ति पत्र प्रदान किए, जिनमें 17 विशेष शिक्षक भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की कि सभी युवा शिक्षक राज्य में शिक्षा का स्तर बेहतर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि आज से आपके कंधों पर उत्तराखंड के भविष्य को संवारने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आ गई है। जब किसी बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और संस्कारयुक्त शिक्षा मिलती है, तो वह केवल अपना जीवन ही नहीं संवारता, बल्कि समाज और राष्ट्र के निर्माण में भी अमूल्य योगदान देता है। शिक्षक देश के उज्ज्वल भविष्य के शिल्पकार हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा देने के साथ-साथ उनमें समाज, संस्कृति और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की भावना भी विकसित करें, जिससे वे शिक्षा के साथ संस्कारवान और जिम्मेदार नागरिक भी बनें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विद्यालयों के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने से लेकर डिजिटल शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण और कौशल विकास तक हर स्तर पर व्यापक सुधार किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पिछले साढ़े चार वर्षों में 28 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। यह केवल आंकड़ा नहीं, बल्कि हमारे युवाओं के आत्मसम्मान की जीत है। इन साढ़े चार वर्षों में जितनी नौकरियां युवाओं को मिली हैं, वह राज्य गठन के बाद और पूर्ववर्ती सरकारों के समय से दो गुना से भी अधिक है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य से किसी को खिलवाड़ नहीं करने देगी। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि पिछले साढ़े चार साल में शिक्षा विभाग में 11 हजार 500 से अधिक नियुक्तियां प्रदान की गई हैं। 3 हजार 500 से अधिक विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। राज्य में शिक्षा में नवाचार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

इस अवसर पर शिक्षा महानिदेशक दीप्ति सिंह, निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉ. मुकुल कुमार सती, निदेशक प्राथमिक शिक्षा अजय नौडियाल, निदेशक अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण वंदना गर्ब्याल, अपर निदेशक कंचन देवराड़ी उपस्थित थे।

शिक्षकों के बीच पहुंचे सीएम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नियुक्ति पाने वाले तमाम शिक्षकों के बीच पहुंचे। उनके साथ ग्रुप फोटो कराई और उनकी खुशी को सांझा किया। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सभी ने कर्तव्यधर्म निभाने की अपेक्षा जताई।

मतभेदों को परे रख विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एकजुट होकर काम करें सांसद : मुर्मु

नयी दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने राष्ट्रहित को सर्वोपरि बताते हुए सांसदों से राजनीतिक मतभेदों को परे रखकर विकसित भारत जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर आम सहमति से काम करने और देश के विकास को नयी ऊर्जा देने का पुरजोर आह्वान किया है।

श्रीमती मुर्मु ने संसद के बजट सत्र के पहले दिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अपने अभिभाषण में कहा कि राष्ट्र से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सांसदों का एकमत होना जरूरी है और यही संविधान की भावना भी है। उन्होंने अपने संबोधन में सरकार के पिछले 11 वर्षों के कार्यकाल में देश के विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से प्रगति करने का उल्लेख करते हुए कहा कि देश तेजी से हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ रहा है। उन्होंने रक्षा , स्वास्थ्य , शिक्षा,

अंतरिक्ष , ढांचागत निर्माण और कृषि आदि क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियों का विशेष तौर पर जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार मिटाने और सामाजिक न्याय तथा महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य किसी एक सरकार या पीढी तक सीमित नहीं है यह एक सतत यात्रा है जिसमें सभी के प्रयास और निरंतरता का महत्व है। उन्होंने कहा, ' विभिन्न मतों और अलग - अलग विचारों के बीच, यह सर्वमान्य है कि राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं। विकसित भारत का संकल्प, भारत की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता, स्वदेशी का अभियान, एकता के लिए प्रयास, स्वच्छता, राष्ट्र से जुड़े ऐसे विषयों पर, सांसदों को एकमत होना ही चाहिए और यही संविधान की भावना भी है। '

श्रीमती मुर्मु ने महात्मा गांधी, पंडित नेहरू , बाबा साहेब और सरदार पटेल से लेकर जेपी , लोहिया , पंडित दीन दयाल उपाध्याय, अटल बिहारी बाजपेयी जैसे महापुरुषों का उल्लेख करते हुए कहा, ' ये सभी इसी विचार के रहे कि लोकतंत्र में विषयों पर मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन कुछ विषय मतभेदों से परे हैं। इसलिए मेरा आज आप सभी से आग्रह है, हर सांसद राष्ट्र हित के विषयों पर एकमत होकर, देश की प्रगति का हिस्सा बनकर चर्चा करें, देश की प्रगति में नई ऊर्जा भरें।' उन्होंने कहा कि देश इस समय भविष्य के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। आज के निर्णयों का का प्रभाव आने वाले वर्षों में दिखाई देगा। उन्होंने कहा, ' इस यात्रा में हम सभी के प्रयास, अनुशासन और निरंतरता का महत्व है। देश की प्रगति हमारे सामूहिक संकल्पों से ही होगी। मुझे विश्वास है कि संसद, सरकार और नागरिक, तीनों मिलकर विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करेंगे। हम भारतवासी राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए संवैधानिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए सरकार, 'रिफ़ॉर्म एक्सप्रेस' की गति को निरंतर तेज करती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार और घोटालों से मुक्त व्यवस्था का निर्माण करने में सफल हो रही है। इससे करदाताओं की एक-एक पाई देश के विकास और जनकल्याण में खर्च हो रही है। उन्होंने कहा कि आज भारत भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। जल-थल-नभ, हर क्षेत्र में भारत की तेज गति आज विश्व में चर्चा का विषय है। श्रीमती मुर्मु ने माओवादी आतंक पर कार्रवाई में सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्षों तक 126 जिलों में असुरक्षा, भय और अविश्वास का वातावरण था। सुरक्षा बलों की कार्रवाई से ऐसे जिलों की संख्या घटकर आठ जिलों तक सिमट गई है।

जिला पंचायत उपाध्यक्ष के भाई समेत दो को मारी गोली, छह लोगों पर मुकदमा दर्ज

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

जिला पंचायत उपाध्यक्ष हरिद्वार अमित चौहान के छोटे भाई सचिन चौहान समेत दो लोगों को गोली लगने की सूचना से इलाके में दहशत फैल गई। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए मेला अस्पताल ले जाया गया जहां से उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। जहां दोनों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना का बारीकी से निरीक्षण किया और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घटना के बाद आरोपी अतुल चौहान खुद थाने पहुंचा और अपना पिस्टल पुलिस को सरेंडर कर दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। गोलीकांड में जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित चौहान के भाई सचिन चौहान के पेट में एक गोली जबकि कृष्णपाल के तीन गोली लगना बताया जा रहा है। घटना सुबह करीब दस बजे की है। नूरपुर पंजनहेड़ी निवासी अमित चौहान जिला पंचायत उपाध्यक्ष है तथा प्रॉपर्टी कारोबारी है। अमित के द्वारा जियापोता जमालपुर मार्ग पर एक कालोनी विकसित की जा रही है। यह कॉलोनी एचआरडीए से स्वीकृत है। जबकि कुछ हिस्सा खाली है। जिस पर प्लाटिंग नही की गई है। बुधवार सुबह कॉलोनी के समीप की जमीन की पैमाइश के लिए जिला प्रशासन की टीम आनी थी। क्षेत्र के पटवारी मौके पर पहुंच गए थे। इसी दौरान नूरपुर पंजनहेड़ी गांव का ही अतुल चौहन अपने भतीजे तरूण चौहान व अन्य साथियों के साथ पहुंचा। अमित चौहान का आरोप है कि अतुल चौहान व तरूण ने हमला करते हुए उन पर गोली चला दी। कई राउंड गोली चलायी गई। गोली लगने से उनका भाई सचिन चौहान और वहां मौजूद कृष्णपाल घायल हो गए। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित चौहान का कहना है कि हमलावरों की गोली से वह बाल बाल बच गए। गोली चलने से अफरातफरी मच गई। घायलों को अस्पताल लेकर जाया गया तथा मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। घटना की जानकारी मिलने पर एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह अस्पताल पहुंचे। कनखल पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। फोरेंसिक टीम भी बुलायी गई, मौके से गोली के चार खोखे बरामद हुए हैं। दोनों पक्ष एक ही गांव नूरपुर पंजनहेड़ी के होने के कारण गांव में एतिहातन पुलिस तैनात की गई है। घटना को लेकर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच झगड़ा होता दिख रहा है। इसके अलावा घटना वहां पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हो गई है। एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि घटना को लेकर जांच की जा रही है, प्रथम दृष्टया आपसी रंजिश की बात सामने आयी है। सीसीटीवी फुटेज की जांच से सच सामने आएगा। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। घायलों को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। वहीं इस घटना के बाद आरोपी अतुल चौहान स्वयं कनखल थाने पहुंचा और अपनी पिस्टल पुलिस के पास जमा करा दी। उसने पुलिस को बताया कि दूसरे पक्ष ने पहले उन पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया। जिस पर उसने अपने बचाव के लिए अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली चलायी। अतुल चौहान ने अपना एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिसमें उसने बताया कि उसने दूसरे पक्ष से अपनी जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उसकी नहीं सुनी। बताया कि उन्होंने पंचायत और सरकारी जमीन की भूमियों पर अवैध कब्जों की शिकायत की थी। गोली आत्मरक्षा में चलाई है। कनखल थाना प्रभारी मनोहर रावत ने बताया कि पिस्ट्रल को सील कर दिया गया है। जबकि अतुल को हिरासत में रखा है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित चौहान का कहना है कि विकसित की जा रही है कालोनी में अवैध जमीन कब्जाने का आरोप लगाया जा रहा है, जबकि इस संबंध में एचआरडीए भी जांच कर चुका है, जांच में कुछ गलत नहीं मिला। आज भी जिला प्रशासन की टीम को जमीन की पैमाइश के लिए आना था, इसी दौरान आरोपी पक्ष वहां पहुंचा और उसने इस घटना को अंजाम दिया।

चार राज्यों के अध्ययन भ्रमण पर जाएंगे रेशम बुनकर: डॉ धन सिंह रावत

पथ प्रवाह, देहरादून

उत्तराखंड को-ऑपरेटिव रेशम फेडरेशन द्वारा प्रदेश के रेशम बुनकरों को चार राज्यों में अध्ययन भ्रमण पर भेजा जाएगा, ताकि वे आधुनिक तकनीक, नवीन डिज़ाइन और उन्नत रेशम उत्पादन प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकें। यह घोषणा माननीय सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने देहरादून स्थित राजपुर रोड पर दून सिल्क के चौथे रिटेल आउटलेट के शुभारंभ अवसर पर की। डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि अध्ययन भ्रमण से रेशम बुनकरों की कार्यक्षमता और दक्षता में वृद्धि होगी तथा वे देश के अन्य राज्यों में अपनाई जा रही श्रेष्ठ तकनीकों को उत्तराखंड में लागू कर सकेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह भ्रमण कार्यक्रम पूरी तरह सुनियोजित और उद्देश्यपूर्ण हो, जिससे बुनकरों को इसका अधिकतम लाभ मिल सके। कार्यक्रम के दौरान सहकारिता मंत्री ने रेशम बुनकरों से सीधा संवाद भी किया। उन्होंने बुनकरों से प्रश्न किया कि क्या रेशम फेडरेशन उनके साथ पारदर्शिता और ईमानदारी से कार्य कर रही है। इस पर उपस्थित बुनकरों ने एक स्वर में फेडरेशन की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन, भुगतान व्यवस्था और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पूर्ण पारदर्शिता बरती जा रही है, जिसका सीधा लाभ उन्हें मिल रहा है। डॉ. रावत ने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में प्रदेश सरकार पारदर्शिता, जवाबदेही और किसानों-बुनकरों के हित को सर्वोपरि रखते हुए कार्य कर रही है, जिससे जमीनी स्तर पर सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान बुनाई कार्यशाला का आयोजन किया गया तथा सिल्क समग्र परियोजना के अंतर्गत लाभार्थियों को चेक एवं प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर 25 कीटपालकों को चेक वितरित किए गए, जबकि बुनाई क्षेत्र से जुड़े लाभार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। फेडरेशन के प्रबंध निदेशक आनंद शुक्ल ने बताया कि रेशम फेडरेशन का लक्ष्य प्रदेश की 10,000 महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में सशक्त बनाना है। उन्होंने जानकारी दी कि आज दून सिल्क के चौथे आउटलेट का शुभारंभ किया गया है तथा शीघ्र ही प्रदेश के अन्य शहरों में छह और आउटलेट खोले जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि आगामी वर्ष में फेडरेशन द्वारा ?10 करोड़ के कारोबार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस अवसर पर निदेशक रेशम प्रदीप कुमार, पूर्व अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह, महाप्रबंधक मातबर कंडारी सहित बड़ी संख्या में महिला बुनकर एवं रेशम फेडरेशन से जुड़े कीटपालक लाभार्थी उपस्थित रहे।

एक नजर

नाबालिग बालिका का अपहरण कर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को चन्द घंटों में पकड़ा

पथ प्रवाह, हरिद्वार। नाबालिग बालिका के अपहरण और उसके साथ छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस ने चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ पीड़िता के पिता ने कोतवाली ज्वालापुर पुलिस में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। कोतवाली ज्वालापुर हरिद्वार को दी गई तहरीर में आरोप लगाया गया था कि वादी की नाबालिग पुत्री को 26 जनवरी को आरोपी अपने साथ स्कूटी में बैठाकर नहर किनारे एकान्त जगह ले गया और वहां उसके साथ गलत हरकत कर छेड़छाड़ की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद हरिद्वार द्वारा मामले की गम्भीरता को देखते हुए तत्काल आरोपी की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक ज्वालापुर को निर्देशित किया गया। प्रभारी निरीक्षक ज्वालापुर द्वारा तत्काल आरोपी की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश गये। पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रेम जोशी पुत्र स्वर्गीय राम दत्त जोशी निवासी राजीव नगर कॉलोनी, आर्य नगर, कोतवाली ज्वालापुर को पकड़ लिया। पुलिस टीम में उप निरीक्षक सोनम रावत, कांस्टेबल अंकित कवि, कांस्टेबल दीपक चौहान मौजूद रहे।

तीर्थ नगरी को साफ स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए निरंतर हो रहा कार्य, 2 माह 11 दिन से चल रहा अभियान

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

तीर्थ नगरी हरिद्वार को साफ स्वच्छ, सुंदर जनपद बनाए जाने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर जनपद में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित स्वयं सफाई अभियान की निगरानी कर रहे हैं। 2 माह 11 दिन से निरंतर सफाई अभियान शहर से लेकर गांव कस्बों तक चलाया जा रहा है, जिसका असर अब धरातल पर दिखने लगा है।

जनपद को साफ स्वच्छ बनाने की दिशा में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित निरंतर प्रयासरत है, सफाई अभियान में ओर तेजी लाने के लिए जिलाधिकारी द्वारा जिला स्तरीय अधिकारियों का विभागवार रोस्टर तैयार करते हुए 31 जनवरी तक जनपद में महा स्वच्छता अभियान पखवाड़ा चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए है कि स्वच्छता अभियान में जो जिम्मेदारी एवं दायित्व जिस अधिकारी को सौंपी गई है वह अपने दायित्वों का निर्वहन संवेदनशीलता के साथ करेंगे,जिससे कि तीर्थनगरी को साफ स्वच्छ,सुंदर जनपद बनाया जा सके। बुधवार को नगर निगम द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र सीतापुर वार्ड नंबर 7 के समीप फैली गंदगी का संज्ञान लेते हुए तत्काल कराई गई साफ सफाई। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा रावत ने अवगत कराया है कि भुवेश्वरी महिला आश्रम एवं आईटीसी सुनहरा कल संस्था के परियोजना निर्देशक डॉ हीरा बल्लभ पंत ने अवगत कराया गया कि वार्ड नंबर 07 सीतापुर आंगनवाड़ी के समीप काफी गंदगी पड़ी है, बच्चों के स्वास्थ्य के दृष्टिगत सफाई का अनुरोध किया गया। उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी सहायक नगर आयुक्त को दी गई जिन्होंने तत्काल संज्ञान लेते हुए सीतापुर क्षेत्र की साफ सफाई कराई गयी।उन्होंने आपदा प्रबंधन अधिकारी ने भुवेश्वरी महिला आश्रम एवं आईटीसी सुनहरा कल के सदस्यों से अपेक्षा की है उक्त क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा कूड़ा कचरा न फेंका जाए, इसके लिए स्थानीय लोगोंको जागरूकता अभियान चलाने के लिए कहा गया। खण्ड विकास अधिकारी खानपुर ने अवगत कराया कि ग्राम पंचायत खानपुर तुगलपुर क्षेत्रांतर्गत सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान 08 कुंटल कूड़ा कचरा एकत्रित किया गया।जिसको उचित निस्तारण हेतु कम्पोस्ट सेंटर भेजा गया। खण्ड विकास अधिकारी रूड़की ने अवगत कराया कि ग्राम पंचायत नन्हेडा अनंतपुर नजुमपुर पानियली क्षेत्रांतर्गत साफ़ सफाई के साथ साथ नालियों की सफाई का कार्य किया गया।

एक नजर

सीएमटीसी सेंटर का मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्र ने किया शुभारंभ

पथ प्रवाह, हरिद्वार। मुख्य विकास अधिकारी डॉ ललित नारायण मिश्र ने भगवानपुर स्थित कम्युनिटी मैनेज ट्रेनिंग सेंटर (CMTC) का फीता काटकर उद्घाटन किया। खंड विकास अधिकारी भगवानपुर आलोक गार्गेय ने बताया कि सीएमटीसी सेंटर मॉडल सीएलएफ ज्योतिर्मय बहुउद्देशीय स्वायत्त सहकारिता द्वारा संचालित है। केंद्र पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जो कि एनसीआरपी प्रीति जोशी द्वारा दिया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने सीएमटीसी सेंटर का निरीक्षण करते हुए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं एवं प्रशिक्षणार्थियों से संवाद किया। उन्होंने महिलाओं को आजीविका संवर्धन, बाजार से जुड़ाव (मार्केट लिंकेज), नए एवं नवाचार आधारित उद्यमों को अपनाने तथा आपसी अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान क्लाउड किचन के संचालन के संबंध में महिला समूह की सदस्यों ने मुख्य विकास अधिकारी से वार्ता की। कार्यक्रम के अवसर पर खण्ड विकास अधिकारी भगवानपुर, जिला थीमेटिक एक्सपर्ट सूरज कुमार, मुख्यमंत्री उद्यम शाला से राव आस्कर, ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई भगवानपुर के कार्मिक उपस्थिति रहे।

बैरागी कैंप स्थित टैंट गोदाम में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू

पथ प्रवाह, हरिद्वार। बुधवार को बैरागी कैंप स्थित एक टैंट हाऊस में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भंयकर थी कि दूर तक धूंए का गुब्बार उठता दियाखी दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से हुए नुकसान का अभी पता नहीं चल सका है। जानकारी के मुताबिक बुधवार दोपहर के समय टैंट के गोदाम में अचानक आग लग गयी। टैंट गोदाम प्रकाश टैंट हाऊस का बताया गया है। आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गयी। आग की सूचना तत्काल दमकल को दी गयी। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की टीम आग बुझाने में जुट गई। मौके पर तीन फायर टेंडर मायापुर फायर स्टेशन से और एक सिडकुल से मंगाया गया। आग की भयावहता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि धुंए का गुब्बार कई किलोमीटर दूर तक दिखायी दिया। आग के कारणों को अभी पता नहीं चल पाया है। दमकल अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही आग लगने के कारण और आग से हुए नुकसान का पता चल सकेगा। इस दौरान धुएं की वजह से आसपास के लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह काबू पाया गया।

गुरु रविदास जयंती की तैयारी में जुटी पुलिस ने की शांति समिति की बैठक

पथ प्रवाह, हरिद्वार। आगामी गुरु रविदास जयंती को शांति एवं सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार के निर्देशों के अनुपालन में थाना खानपुर परिसर में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस बैठक में क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों, गुरु रविदास पंथ के अनुयायियों और ग्राम चौकीदारों ने प्रतिभाग किया। गोष्ठी के दौरान सभी से अपील की गई कि जयंती के दौरान आयोजित प्रार्थना सभाओं, भक्ति गीतों और नगर कीर्तनों को आपसी भाईचारे के साथ मनाएं। कार्यक्रम के दौरान किसी भी व्यक्ति, धर्म या संप्रदाय के विरुद्ध कोई भी ऐसी टिप्पणी न की जाए जिससे सामाजिक समरसता, धार्मिक सहिष्णुता या राष्ट्रीय एकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। जुलूस या कार्यक्रमों में मांस-मदिरा का सेवन पूर्णतः वर्जित रहेगा। साथ ही आग्नेयास्त्र, लाठी-डंडा, खुकरी, तलवार, तेज धारदार हथियार, पटाखे या किसी भी प्रकार के विस्फोटक सामग्री के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यातायात नियमों का पालन करने और मार्ग व्यवस्था में पुलिस का सहयोग करने के निर्देश दिए गए ताकि जनसाधारण को असुविधा न हो। बैठक के अंत में उपस्थित सभी नागरिकों ने प्रशासन को आश्वस्त किया कि वे पर्व को पूर्ण गरिमा और नियमों के दायरे में रहकर मनाएंगे।

डीएम मयूर दीक्षित ने किया जिले में प्रशासनिक फेरबदल

पथ प्रवाह, हरिद्वार। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने शासन के निर्देश पर जिले में प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल किया है। फेरबदल के बाद कई अधिकारियों को नई तैनाती दी गई है। इस बदलाव से प्रशासनिक कामकाज और सुगम होगा।

जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार हरिद्वार जनपद में डिप्टी कलेक्टर के पद पर तैनात अनिल कुमार शुक्ला (पीसीएस) को अपर उप जिलाधिकारी रुड़की के पद पर तैनात किया गया है। वहीं डिप्टी कलेक्टर एवं उप मेलाधिकारी कुंभ मेला हरिद्वार के पद पर तैनात आकाश जोशी (पीसीएस) को विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी हरिद्वार, प्रभारी अधिकारी आपदा एवं प्रभारी अधिकारी भूलेख के पदों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही डिप्टी कलेक्टर हरिद्वार एवं अपर मेलाधिकारी कुंभ मेला हरिद्वार के पद पर तैनात दयानंद सरस्वती को डिप्टी कलेक्टर हरिद्वार एवं विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के पद से कार्यमुक्त कर दिया गया है।

एचआरडीए ने धर्मशाला परिसर का अवैध निर्माण किया सील

पथ प्रवाह, हरिद्वार

खड़खड़ी क्षेत्र अंतर्गत शमशान घाट रोड पर निर्धन निकेतन के समीप स्थित ओम आश्रम की पूर्व निर्मित धर्मशाला में किए जा रहे अवैध निर्माण पर प्राधिकरण ने सख्त कार्रवाई की गई। प्राधिकरण की टीम ने पुलिस बल की उपस्थिति में मौके पर पहुंचकर अनाधिकृत रूप से किए जा रहे निर्माण कार्य को सील कर दिया। जानकारी के अनुसार धर्मशाला परिसर में लगभग 50म40 फीट बाई ओर, 18म40 फीट सामने की ओर तथा 100म80 फीट दाई ओर क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण कार्य किया जा रहा था। निर्माण कार्य की जानकारी मिलने पर प्राधिकरण की टीम द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया, जिसमें निर्माण को नियमों के विपरीत पाया गया। कार्रवाई के दौरान मौके पर उपस्थित अनाधिकृत निर्माणकर्ता एवं प्रबंधक ओम आश्रम रणछोड़ सिंह को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जब तक सक्षम प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत न हो जाए, तब तक किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न किया जाए। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि निर्देशों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में नियमानुसार कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि शहर में अवैध निर्माण पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और बिना अनुमति किए जा रहे किसी भी निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आमजन से भी अपील की गई है कि किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व संबंधित प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत अवश्य कराएं।

24 कैरेट गोल्ड पौंने दो लाख के पार, मध्यम वर्ग के लोगों की पहुंच से बाहर

पथ प्रवाह, हरिद्वार

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जारी अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग के बीच सोने की कीमतें अपने अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई हैं। भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,73,000 प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर गया है, जिससे निवेशकों और व्यापारियों में हलचल तेज हो गई है। यह अब तक का सर्वकालिक उच्च स्तर माना जा रहा है। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमतें 1,57 हजार भी रिकॉर्ड बढ़त के साथ कारोबार कर रही हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंका, भू-राजनीतिक तनाव, डॉलर में कमजोरी और प्रमुख देशों की मौद्रिक नीतियों को लेकर असमंजस ने सोने को मजबूती दी है। इसके अलावा, कई देशों के केंद्रीय बैंक लगातार सोने की खरीद कर रहे हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग और बढ़ गई है। घरेलू बाजार में सोने की बढ़ती कीमतों का असर आभूषण उद्योग पर साफ दिखाई दे रहा है। शादी-विवाह और त्योहारों के मौसम के बावजूद आम खरीदारों की खरीदारी प्रभावित हुई है, हालांकि निवेश के लिहाज से लोग अब भी सोने को सुरक्षित विकल्प मान रहे हैं। आर्थिक जानकारों का मानना है कि यदि वैश्विक हालात में जल्द सुधार नहीं हुआ तो सोने की कीमतें आने वाले समय में और नए रिकॉर्ड बना सकती हैं। वहीं निवेशकों को सतर्कता और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निवेश करने की सलाह दी जा रही है।

हरिद्वार के जेवर ज्वैलर्स शोरूम के मालिक गौरव मित्तल ने बताया कि सोना अभी ओर महंगा होगा। जिसके चलते बाजार में गिरावट आई है। शादी के लिए जरूरी गहने ही लोग खरीद रहे है।

बहुउद्देशीय शिविर में 987 लोगों को किया गया योजना से लाभान्वित

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की दीपक रामचंद्र सेट की अध्यक्षता में विकास खंड रूड़की के न्याय पंचायत तांशीपुर पंचायत भवन परिसर तांशीपुर में जन-जन की सरकार जन-जन के द्वार अभियान के अंतर्गत बहुउद्देशीय शिविर आयोजन किया गया। बहुउद्देशीय शिविर में 1108 लोगों को विभिन्न विभागों से प्रमाण पत्र निर्गत किए गए तथा 987 लोगों विभिन्न विभागों की संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। इस शिविर में 6273 लोगों ने प्रतिभाग किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देशराज कर्णवाल, उपाध्यक्ष, (राज्यमंत्री स्तर) समाज कल्याण योजनाएं अनुश्रवण समिति ने कहा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार प्रदेश की सभी न्याय पंचायतों में यह अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र नागरिकों तक पहुंचाना तथा उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। शिविर के दौरान क्षेत्रवासियों द्वारा 67 समस्याएं दर्ज कराई गईं। इनमें से 34 समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा किया गया, जबकि शेष समस्याओं के शीघ्र समाधान हेतु उन्हें संबंधित विभागों को प्रेषित किया गया।

इस अवसर पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की दीपक रामचंद्र सेठ ने सभी संबंधित अधिकारियों को क्षेत्रवसियों की समस्याओं का शीघ्रता से निस्तारण करने के निर्देश दिए और जिन शिकायतों का जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में निस्तारित नहीं हो पाया है उन शिकायतों का तत्परता से निराकरण करना सुनाश्चित करे। इस अवसर पर विधायक झबरेडा वीरेंद्र जाति, प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा अनीस गौड़, मंडल अध्यक्ष भाजपा आशीष कुमार, क्षेत्र पंचायत सदस्य ओम सिंह, अंकुर कुमार, खंड विकास अधिकारी लक्सर सुमन कोटियाल सहित समस्त ग्राम प्रधानगण, पंचायत सदस्यगण, अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे।

संपादकीय

आसमान छू रहा सोना और चांदी दिखा रही चमक

हाल के दिनों में सोना और चांदी ने जिस तरह नई ऊँचाइयों को छुआ है, उसने न सिर्फ निवेशकों बल्कि आम जनता का भी ध्यान अपनी ओर खींचा है। सोना जहाँ ऐतिहासिक स्तर पर पहुँच चुका है, वहीं चांदी भी अपनी चमक से बाजार में हलचल मचा रही है। वैश्विक और घरेलू परिस्थितियों का मिला-जुला असर इन कीमती धातुओं की कीमतों में तेज़ उछाल के रूप में सामने आया है।

वैश्विक स्तर पर देखें तो भू-राजनीतिक तनाव, युद्ध की आशंकाएँ, महंगाई का दबाव और विकसित देशों में ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता ने निवेशकों को सुरक्षित विकल्पों की ओर मोड़ा है। ऐसे समय में सोना सदियों से 'सेफ हेवन' माना जाता रहा है। डॉलर में उतार-चढ़ाव और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अस्थिरता भी सोने की कीमतों को ऊपर ले जाने में अहम भूमिका निभा रही है। चांदी, जो औद्योगिक उपयोग के साथ-साथ निवेश का साधन भी है, हरित ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों और सोलर पैनलों की बढ़ती मांग के कारण अतिरिक्त समर्थन पा रही है।

घरेलू परिदृश्य में भी हालात कुछ अलग नहीं हैं। भारत में रुपये की कमजोरी, आयात शुल्क, त्योहारी सीजन और शादी-विवाह की मांग ने सोने-चांदी की कीमतों को और मजबूती दी है। आम भारतीय परिवार के लिए सोना न सिर्फ आभूषण बल्कि बचत और सुरक्षा का प्रतीक है। यही कारण है कि कीमतें बढ़ने के बावजूद मांग पूरी तरह कमजोर नहीं पड़ी है, बल्कि निवेश के रूप में इसमें रुचि और बढ़ी है।

हालाँकि, इस तेजी का दूसरा पहलू भी है। लगातार बढ़ती कीमतों ने मध्यम वर्ग और छोटे कारोबारियों पर दबाव बढ़ाया है। आभूषण उद्योग में लागत बढ़ने से बिक्री प्रभावित हो सकती है, वहीं आम उपभोक्ता के लिए सोना-चांदी खरीदना पहले से अधिक महँगा हो गया है। ऐसे में निवेशकों को भी भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि सोच-समझकर कदम उठाने की जरूरत है।

देखा जाए तो सोना और चांदी की यह चमक केवल बाजार का उतार-चढ़ाव नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की अनिश्चितता का संकेत है। यह सरकारों और नीति-निर्माताओं के लिए भी चेतावनी है कि आर्थिक स्थिरता और विश्वास बहाली के लिए ठोस कदम उठाए जाएँ। आम नागरिकों के लिए संदेश स्पष्ट है–कीमती धातुएँ सुरक्षा का माध्यम हैं, लेकिन अंधाधुंध निवेश जोखिम भरा हो सकता है। संतुलन, विवेक और दीर्घकालिक सोच ही इस चमक में वास्तविक लाभ दिला सकती है।

अजित पवार: आरोपों से ऊपर उठे राजनीति के 'दादा-पुरुष'

ललित गर्ग

यह खबर केवल एक व्यक्ति के निधन की नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति के एक पूरे युग के अचानक थम जाने की सूचना है। 28 जनवरी 2026 की सुबह जब बारामती में हुए विमान हादसे में उपमुख्यमंत्री अजित अनंतराव पवार के असामयिक निधन की पुष्टि हुई, तो वह क्षण केवल पवार परिवार के लिए नहीं, बल्कि समूचे महाराष्ट्र और देश की राजनीति के लिए गहरे शोक और स्तब्धता का कारण बन गया। जिस नेता को लोग अधिकार, अनुभव और निर्णय क्षमता का पर्याय मानते थे, उसका इस तरह अचानक चले जाना सत्ता, प्रशासन और राजनीतिक संतुलन में एक बड़ा रिक्त स्थान छोड़ गया है। एक संभावनाओं भरी महाराष्ट्र की राजनीति एवं राष्ट्रीय विचारों का सफर ठहर गया, उनका निधन न केवल महाराष्ट्र के लिये, भारत की राष्ट्रवादी सोच के लिये बल्कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रवादी राजनीति पर एक गहरा आघात है, अपूरणीय क्षति है। उनके निधन से सहकारी आन्दोलन को भी गहरा धक्का लगा है।

अजित पवार का जीवन किसी राजसी विरासत की सहज कहानी नहीं था। 22 जुलाई 1959 को अहमदनगर जिले के देओली प्रवरा क्षेत्र में जन्मे अजित पवार ने जीवन को बहुत करीब से संघर्ष करते हुए देखा। उनके पिता अनंतराव पवार फिल्म जगत से जुड़े रहे, राजकमल स्टूडियो में काम किया, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियां साधारण रहीं। औपचारिक शिक्षा माध्यमिक स्तर तक ही सीमित रही, किंतु जीवन की व्यावहारिक पाठशाला ने उन्हें वह सिखाया जो बड़े-बड़े शैक्षणिक संस्थान भी नहीं सिखा पाते। शायद यही कारण रहा कि अजित पवार की राजनीति किताबों से नहीं, जमीन से निकली हुई राजनीति थी, जिसमें किसानों की पीड़ा, सहकारी संस्थाओं की ताकत और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नब्ज साफ दिखाई देती थी। राजनीति में उनका प्रवेश किसी बड़े मंच से नहीं, बल्कि सहकारी आंदोलन की प्रयोगशाला से हुआ। 1982 में मात्र बीस वर्ष की आयु में उन्होंने एक चीनी सहकारी संस्था का चुनाव लड़ा। यह वही दौर था जब महाराष्ट्र की राजनीति में सहकारी संस्थाएं सत्ता की रीढ़ मानी जाती थीं। अजित पवार ने बहुत जल्दी समझ लिया कि यदि ग्रामीण महाराष्ट्र को साधना है तो उसे बैंक, चीनी मिल, सिंचाई और बिजली से जोड़ना होगा। यही समझ आगे चलकर उनकी राजनीतिक पहचान की सबसे बड़ी ताकत बनी। 1991 अजित पवार के राजनीतिक जीवन का निर्णायक वर्ष रहा। पुणे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष बनने के साथ ही उन्होंने वित्तीय प्रशासन और संगठन संचालन में अपनी दक्षता का परिचय दिया। सोलह वर्षों तक इस पद पर बने रहना अपने आप में उनकी विश्वसनीयता और पकड़ को दर्शाता है। उसी वर्ष बारामती से लोकसभा के लिए निर्वाचित होना उनके बढ़ते कद का प्रमाण था, लेकिन उन्होंने यह सीट अपने चाचा शरद पवार के लिए छोड़ दी। यह फैसला केवल पारिवारिक निष्ठा का नहीं, बल्कि राजनीतिक दूरदृष्टि का भी उदाहरण था। इसके बाद विधानसभा में प्रवेश और फिर लगातार बारामती से जीत ने उन्हें जनाधार का वह आधार दिया, जिसे महाराष्ट्र की राजनीति में विरले ही कोई चुनौती दे सका। अजित पवार को सत्ता के गलियारों में पहुंचाने वाली सबसे बड़ी विशेषता उनकी प्रशासनिक पकड़ थी। कृषि, बागवानी, बिजली और जल संसाधन जैसे कठिन और संवेदनशील विभागों को संभालते हुए उन्होंने विकास और विवाद दोनों को नजदीक से जिया। जल संसाधन मंत्री के रूप में कृष्णा घाटी और कोकण सिंचाई परियोजनाओं से उनका नाम जुड़ा। इन परियोजनाओं ने जहां किसानों के लिए पानी और उम्मीद का संदेश दिया, वहीं आलोचनाओं और आरोपों का बोझ भी उनके कंधों पर रखा। इसके बावजूद वे उन नेताओं में रहे जो फाइलों से नहीं, फैसलों से पहचाने जाते थे।

उपमुख्यमंत्री के रूप में उनका सफर महाराष्ट्र की राजनीति में एक अनोखा अध्याय है। छह बार इस पद तक पहुंचना केवल राजनीतिक संयोग नहीं था, बल्कि सत्ता संतुलन, गठबंधन राजनीति और संगठनात्मक ताकत का परिणाम था। वे सरकार में अक्सर संकटमोचक की भूमिका में दिखे। बजट, वित्तीय प्रबंधन और संसदीय रणनीति में उनकी पकड़ ऐसी थी कि विरोधी भी उनके अनुभव को नजरअंदाज नहीं कर पाते थे। उन्हें महत्वाकांक्षी कहा गया, कभी-कभी कठोर और रूखे स्वभाव का नेता भी बताया गया, लेकिन यह भी सच है कि सत्ता की वास्तविकता को वे भावनाओं से नहीं, निर्णयों से देखते थे। विवाद उनके राजनीतिक जीवन का अभिन्न हिस्सा रहे। सिंचाई घोटाले से लेकर बयानबाजी तक, कई मौके ऐसे आए जब उनकी छवि पर प्रश्नचिह्न लगे। 'अगर बांध में पानी नहीं है तो क्या पेशाब करके भरें?' जैसे बयान ने उन्हें आलोचनाओं के केंद्र में ला खड़ा किया। उन्होंने माफी भी मांगी, सफाई भी दी और समय के साथ उन विवादों से उबरते हुए फिर सत्ता के शीर्ष पर लौटे। यह उनकी राजनीतिक जिजीविषा का प्रमाण था कि आलोचना और आरोप उन्हें रोक नहीं पाए।

शरद पवार के साथ उनके रिश्ते को लेकर भी हमेशा चर्चाएं रहीं। कभी मतभेद, कभी दूरी और कभी सियासी अलग राह की अटकलें। लेकिन अजित पवार स्वयं को हमेशा शरद पवार का अनुयायी बताते रहे। उन्हें मिला 'दादा' का संबोधन केवल पारिवारिक नहीं था, बल्कि वह एक राजनीतिक ब्रांड बन चुका था, जो उनके समर्थकों में भरोसे और नेतृत्व की भावना जगाता था। वे संगठनकर्ता भी थे और प्रशासक भी, रणनीतिकार भी और जमीनी नेता भी। उन्हें अपनी विविध आयामी भूमिकाओं से अपने को मिले 'दादा' के अलंकरण को सार्थक भी किया और जीवंतता भी दी। उनका असामयिक निधन एक क्रूर विडंबना है। जिस नेता ने दशकों तक सत्ता की उड़ान भरी, उसकी जीवन यात्रा एक विमान हादसे में थम गई। कहा जाता है कि दुर्घटना से कुछ समय पहले तक वे पूरी तरह सक्रिय थे, योजनाओं, बैठकों और राजनीतिक समीकरणों में व्यस्त। यह अचानक आई मृत्यु उस अनिश्चितता को रेखांकित करती है, जो सत्ता और जीवन दोनों के साथ जुड़ी है।

अजित पवार का व्यक्तित्व एवं कृतित्व सफल राजनेता, समाज निर्माता, ग्राम-उद्धारक, सहकारी आन्दोलन पुरोधा, कुशल प्रशासक के रूप में अनेक छवि, अनेक रंग, अनेक रूप में उभरकर सामने आता हैं। आपके जीवन की दिशाएं विविध एवं बहुआयामी थीं। आपके जीवन की धारा एक दिशा में प्रवाहित नहीं हुई, बल्कि जीवन की विविध दिशाओं का स्पर्श किया। यही कारण है कि कोई भी महत्त्वपूर्ण क्षेत्र आपके जीवन से अछूता रहा हो, संभव नहीं लगता। आपके जीवन की खिड़कियाँ समाज एवं राष्ट्र को नई दृष्टि देने के लिए सदैव खुली रही। उनकी सहजता और सरलता में गोता लगाने से ज्ञात होता है कि वे राजनीतिक सरोकार से ओतप्रोत एक अल्हड़ एवं साहसिक व्यक्तित्व थे। बेशक अजित पवार अब इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन अपने जुझारु राजनीति जीवन के दम पर वे हमेशा भारतीय राजनीति एवं राष्ट्रवादी सोच के आसमान में एक सितारे की तरह टिमटिमाते रहेंगे। आज जब महाराष्ट्र और देश उनके निधन पर शोकाकुल है, तब अजित पवार का मूल्यांकन केवल प्रशंसा या आलोचना के तराजू पर नहीं किया जा सकता। वे विवादों से घिरे रहे, लेकिन उनसे परिभाषित नहीं हुए। उनकी राजनीति कठोर थी, लेकिन उसमें अनुभव की गहराई थी।

साहसी पत्रकारिता से आधुनिक मीडिया तक

सुनील कुमार महला

हर वर्ष 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस (इंडियन न्यूज़पेपर डे) के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में इसलिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि 29 जनवरी 1780 को भारत का पहला समाचार पत्र 'हिक्की का गजट', जिसे 'हिक्कीज़ बंगाल गजट' के नाम से भी जाना जाता है, कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। यही कारण है कि इस ऐतिहासिक शुरुआत की स्मृति में 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है।

बहुत से पाठकों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह अख़बार न केवल भारत का, बल्कि पूरे एशिया का पहला मुद्रित (प्रिंटेड) समाचार पत्र था। इसका आधिकारिक नाम 'द बंगाल गजट' अथवा 'कलकत्ता जनरल एडवरटाइज़र' था। इसके संस्थापक, लेखक और प्रकाशक थे-जेम्स ऑगस्टस हिक्की। अपनी बेबाक पत्रकारिता, तीखी टिप्पणियों और स्वतंत्र सोच के कारण यह अख़बार आम लोगों के बीच 'हिक्की गजट' के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यदि इस दिवस के महत्व की बात करें, तो भारतीय समाचार पत्र दिवस स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के महत्व को रेखांकित करता है। यह दिवस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतंत्र की मजबूती और समाज को जागरूक करने में मीडिया की भूमिका का प्रतीक है। दूसरे शब्दों में कहें तो 29 जनवरी पत्रकारिता के इतिहास और लोकतांत्रिक मूल्यों को नमन करने का दिन है। अब यदि हम बंगाल गजट की विशेषताओं पर नज़र डालें, तो यह अख़बार उस दौर में साप्ताहिक रूप से (हर शनिवार) प्रकाशित होता था। इसकी कीमत एक रुपया थी, जो उस समय के हिसाब से काफी महंगी मानी जाती थी। इस अख़बार की सबसे बड़ी पहचान उसका सरकार-विरोधी रुख था। उपलब्ध जानकारियों के अनुसार, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने इसकी शुरुआत से ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया था।अख़बार के शीर्ष पर छपा वाक्य अपने आप में इसकी विचारधारा को स्पष्ट करता है-एक साप्ताहिक राजनीतिक और व्यापारिक पत्र, जो सभी पक्षों के लिए खुला है, लेकिन किसी के प्रभाव में नहीं है। यह कथन अपने आप में स्वतंत्र पत्रकारिता का घोषणापत्र था। यह कहना भी ग़लत नहीं होगा कि बंगाल गजट जितना साहसी था, उतना ही विवादास्पद भी। बहुत कम लोग जानते हैं कि यह अख़बार केवल पारंपरिक 'न्यूज़ पेपर' नहीं था, बल्कि इसमें उस दौर के गॉसिप कॉलम भी प्रमुखता से छपते थे। हिक्की ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के भ्रष्टाचार, प्रेम संबंधों, निजी पार्टियों और सत्ता के दुरुपयोग से जुड़ी चटपटी व सनसनीखेज़ खबरें प्रकाशित करते थे। जब हिक्की ने तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स और उनकी पत्नी पर टिप्पणी करते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, तो ब्रिटिश सरकार बौखला गई। परिणामस्वरूप, हिक्की को जेल भेज दिया गया। लेकिन पत्रकारिता के इतिहास में यह एक अनोखा उदाहरण है कि हिक्की ने जेल के भीतर से भी अख़बार लिखना और छपवाना जारी रखा, जब तक कि अंततः अंग्रेजों ने उनका प्रिंटिंग प्रेस ही जब्त नहीं कर लिया।हिक्की के लिए 'आजादी' का अर्थ केवल भारत की आजादी नहीं था, बल्कि वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (फ्रीडम ऑफ स्पीच) और ब्रिटिश सत्ता की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे थे। इस दृष्टि से वे अपने समय के 'एंटी-एस्टेब्लिशमेंट पत्रकार' कहे जा सकते हैं। बंगाल गजट में प्रकाशित होने वाले विज्ञापन भी अपने आप में बेहद रोचक और उस दौर की सामाजिक सच्चाइयों को उजागर करते थे। इनमें गुमशुदा कुत्तों, बिकने वाले दासों (जो उस समय की कड़वी हकीकत थी), तथा यूरोप से आए ताज़ा पनीर और शराब जैसे विज्ञापन प्रमुखता से छपते थे।अपनी तीखी लेखनी के कारण हिक्की ने वारेन हेस्टिंग्स से गहरी दुश्मनी मोल ले ली। अंततः मार्च 1782 में ब्रिटिश सरकार ने उनका प्रिंटिंग प्रेस जब्त कर लिया और मात्र दो वर्षों के भीतर यह ऐतिहासिक अख़बार बंद हो गया। हिक्की जैसे साहसी पत्रकार का अंत अत्यंत दुखद रहा। प्रेस जब्त होने के बाद वे पूरी तरह कंगाल हो गए। माना जाता है कि उनकी मृत्यु एक जहाज पर हुई और उनके पास अंतिम संस्कार तक के पैसे नहीं थे। आज यदि हम वर्तमान समय में समाचार पत्रों की भूमिका पर दृष्टि डालें, तो स्पष्ट होता है कि समाचार पत्र मनुष्य के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग हैं। वे केवल सूचना का माध्यम नहीं, बल्कि समाज का दर्पण होते हैं। समाचार पत्र राजनीति, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, तकनीक, कृषि, व्यापार, खेल, अनुसंधान, अंतरिक्ष, बैंकिंग और सामाजिक विषयों पर गहन, तथ्यपरक और विश्लेषणात्मक सामग्री प्रदान करते हैं।

अब स्मृतियां ही शेष : और मार्क टली जब भारत की आवाज बन गए

ऋतुपर्ण दवे

एक जांबाज पत्रकार, वो शख्सियत जिसकी विश्वसनीयता ने भारत में विदेशी ब्रॉडकास्टर बीबीसी को वो पहचान दिलाई जो दुनिया में शायद ही किसी को मिली हो। यारों का यार होकर भी रिपोर्टिंग करते वक्त उसूलों से समझौता न करने वाली रिपोर्ट के धनी मार्क टली भारत में ही जन्मे भारत की मिट्टी में आखिरी सांस भी ली। फक गोरा होकर भी भारतीय परिवेश में रंगे टली जब फर्राटेदार कवरेज करते तो बरबस ही मुंह से निकलता ये गोरा कोई कैसा लंदन का। जीवन में जो सादगी, विनम्रता सहजता, संतुलन और सरलता उनमें बेमिशाल थी। दिखावे और ठाठ-बाट से दूर रहने वाले मार्क का जन्म 24 अक्टूबर 1935, टालीगंज, कोलकाता में हुआ और आखिरी सांस देश की राजधानी नई दिल्ली में 25 दिसंबर 2026 को ली।

भारत को लेकर विदेशियों की राय भी प्रायः अलग-अलग रहती है। पत्रकार बिरादरी तो और भी अलग नजरिए से देखती है। भारत को कभी आध्यात्म तो कभी ऐसा देश समझते हैं जहां काफी कुछ ठीक नहीं लगता। लेकिन मार्क का नजरिया भारत के प्रति हमेशा से अलग रहा। उन्होंने न भारत को पर्यटन स्थल समझा और न ही विदेशियों की भांति उपनिवेशवादी मानसिकता से देखा। वो तो एक चलता, फिरता, हाड़मांस का पुतला बनकर भारत में रहे, जो दिखा वही लिखा और कहा। इसी विशेषता ने भारत में इतना भरोसेमंद और लोकप्रिय बना दिया कि एक समय आया और अभी भी है कि कहीं भीतर या मोहल्ले की गुप्त बातें भी साझा होती हैं तो कहा जाता कि बीबीसी लंदन की पक्की खबर है, गलत कैसे होगी! इतनी विश्वनीयता वह भी उस दौर में जब भारतीय मीडिया पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में थी के बहुत कुछ मायने हैं। निश्चित रूप से मार्क टली के निधन से भारत ने अपना एक सच्चा दोस्त खो दिया है।

मार्क टली के पिता एक रईस अंग्रेज थे जो व्यापारिक एजेंसी, गिलैंडर्स एंड अर्बुथनोट में वरिष्ठ भागीदार थे। ये तबकी बहुत बड़ी कंपनी थी जो कोयला खदानों, रेलवे और बीमा कंपनी का काम करती थी। उनकी मां का जन्म बांग्लादेश में हुआ था। बचपन के दस साल भारत में बिताया लेकिन भारतीयों से मिलने-जुलने की उन्हें आजादी नहीं थी। स्कूल शिक्षा खातिर उन्हें इंग्लैंड जाना पड़ा जहां ट्वाईफोर्ड स्कूल, मार्लबोरो कॉलेज और ट्रिनिटी हॉल तथा कैम्ब्रिज में पढ़े। धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। विचार पादरी बनने का था लेकिन दो सत्रों के बाद ही इसे बदला और 1964 में बीबीसी में शामिल हुए।

1960 के दशक में आकाशवाणी का बोलबाला था। मेल्विल डी मेलो जैसे बड़े नाम रेडियो पर राज करते थे। आकाशवाणी और रेडियो सीलोन का दबदबा था। ऐसे में रेडियो प्रसारण में जगह बनाना आसान नहीं था। लेकिन मार्क टली की निष्ठा, लगन थी जो कर दिखाया। तमाम कठिनाइयों, सरकारी दबाव के बावजूद 1965 का भारत-पाकिस्तान युद्ध, 1971 का मुक्ति युद्ध और बांग्लादेश का जन्म, 1975 का आपातकाल, 1980 के दशक का पंजाब विद्रोह और 5 जून, 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार कवर कर न केवल वो खास मुकाम बनाया बल्कि उन्हें इतिहास का प्रत्यक्ष गवाह बनने का मौका भी मिला। अन्य चर्चित कवरेजों में इंदिरा गांधी की हत्या, सिख विरोधी दंगे, राजीव गाँधी की हत्या एवं बाबरी मस्जिद विध्वंस भी रहे। आपातकाल में निष्पक्षता के चलते इन्दिरा गाँधी उन्हें गिरफ्तार करना चाहती थीं तो कुछ दिनों के लिए लंदन चले गए। 1975 के आपातकाल पर उनकी पुस्तक 'इंडियाज अनएंडिंग जर्नी' तो 1978 के प्रयागराज कुंभ का व्यापक कवरेज और उनकी पुस्तक 'नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया' पर इस सबसे बड़े मेले का पूरा वृतांत काफी चर्चाओं में रहा।

मार्क टली को दक्षिण एशिया की पूरी जानकारी और समझ थी। इन देशों में व्यापक भ्रमण और कवरेज किया। जहां भी जाते केवल प्रशासनिक या राजनीतिक जानकारियां भर नहीं जुटाते बल्कि वहां के भू-भाग, सामाजिक ताने-बाने, संस्कृति, रीति-रिवाज भाषा, दाना-पानी, परंपरा और खान-पान से भी जुड़, समझ, उसे अनुभव करते। उनकी सादगी ने उन्हें एक अद्वितीय पत्रकार बनाया। पूरी उम्र उनके व्यक्तित्व में कहीं कोई अहंकार नहीं दिखा। भारतीय वेशभूषा उन्हें बेहद पसंद थी। इतनी कि लंदन जाते तो कई बार विशेष स्थानों पर बिना टाई लगाए ही पहुंच जाते जहां यह अनिवार्य थी। वहां उन्हें रिसेप्शन पर उधार लेनी पड़ता।

वो भारत की सबसे बड़ी ताक़त उसकी स्थिरता को जबकि सबसे बड़ी खूबी विभिन्न धर्मावलंबियों की एकजुटता को मानते रहे। वो भारत को वो भूमि मानते जहां पहाड़, रेगिस्तान, समुंदर के किनारे हैं।

सीएम पुष्कर धामी की कैबिनेट के अहम फैसले: भू-अर्जन प्रक्रिया सरल, ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी

पथ प्रवाह, देहरादून।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित की गई उत्तराखण्ड मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के प्रशासनिक, औद्योगिक, शिक्षा, ऊर्जा एवं आधारभूत संरचना से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन निर्णयों का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना, औद्योगिक विकास को गति देना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना तथा रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट बैठक की विस्तृत जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं/स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को बड़ी राहत देते हुए यह निर्णय लिया कि जिन कर्मचारियों ने अपने मूल संवर्ग में न्यूनतम पाँच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है, उन्हें अपने सम्पूर्ण सेवाकाल में एक बार आपसी समझौते (म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग) के आधार पर जनपद परिवर्तन की अनुमति प्रदान की जाएगी। इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है।

परियोजनाओं हेतु भूमि प्राप्ति की नई प्रक्रिया तय

राज्य में लघु, मध्यम एवं वृहद् परियोजनाओं के लिए भू-स्वामियों से आपसी सहमति के आधार पर भूमि प्राप्ति की प्रक्रिया को कैबिनेट ने मंजूरी दी।

यह प्रक्रिया भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अत्यधिक समय लगने वाली प्रक्रिया के विकल्प के रूप में लाई गई है। इससे मुकदमेबाजी में कमी आएगी तथा जनहित की परियोजनाओं की लागत भी कम होगी।

प्राग फार्म भूमि से जुड़े शासनादेश में संशोधन

जनपद ऊधमसिंहनगर स्थित प्राग फार्म की 1354.14 एकड़ भूमि को औद्योगिक आस्थान विकसित करने हेतु सिडकुल को हस्तांतरित किए जाने संबंधी शासनादेश में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी। संशोधन के तहत औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से राजस्व विभाग की सहमति से समान प्रयोजन हेतु भूमि को उप-पट्टे (सब-लीज) पर देने का अधिकार पट्टेदार को प्रदान किया गया है।

जनजाति कल्याण विभाग का ढांचा पुनर्गठित

जनजाति बहुल जनपद देहरादून, चमोली, ऊधमसिंहनगर एवं पिथौरागढ़ में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए चार जिला जनजाति कल्याण अधिकारियों के पद सृजित किए गए हैं। इन पदों को सेवा नियमावली में शामिल करने हेतु उत्तराखण्ड जनजाति कल्याण राजपत्रित अधिकारी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025 को प्रख्यापित करने पर कैबिनेट ने निर्णय लिया।

भू-जल निकास पर जल मूल्य/प्रभार लागू

राज्य में गैर-कृषिकारी उपयोग हेतु भू-जल के दोहन पर जल मूल्य/प्रभार की दरें तत्काल प्रभाव से लागू करने को कैबिनेट ने मंजूरी दी। यह व्यवस्था उद्योगों, होटल, अपार्टमेंट, वॉटर पार्क, वाहन धुलाई केंद्र, स्वीमिंग पूल आदि पर लागू होगी। वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं रेजीडेंशियल अपार्टमेंट/ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के लिए 5000 का पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया गया है।

देहरादून में निजी विश्वविद्यालय को मंजूरी

राज्य को शिक्षा हब के रूप में विकसित करने की दिशा में कैबिनेट ने जनपद देहरादून में 'जी.आर.डी. उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय' की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की। विश्वविद्यालय का उद्देश्य नवाचारी शिक्षा, शोध, वंचित वर्ग को अवसर प्रदान करना तथा रोजगार सृजन करना है।

चिन्यालीसौड़ व गौचर हवाई पट्टियां रक्षा मंत्रालय को हस्तांतरित

जनपद उत्तरकाशी स्थित चिन्यालीसौड़ एवं चमोली स्थित गौचर हवाई पट्टियों को सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए संयुक्त नागरिक एवं सैन्य उपयोग हेतु एडवांस लैंडिंग ग्राउंड (रत्न) के रूप में लीज आधार पर रक्षा मंत्रालय को हस्तांतरित करने की सहमति कैबिनेट ने दी।

उत्तराखण्ड ग्रीन हाइड्रोजन नीति, 2026 को मंजूरी

राज्य में स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 'उत्तराखण्ड ग्रीन हाइड्रोजन नीति, 2026' के प्रख्यापन को कैबिनेट ने मंजूरी दी। यह नीति राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप है और जल विद्युत जैसे प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से रोजगार सृजन, कार्बन उत्सर्जन में कमी तथा नेट-जीरो लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होगी।

नई आवास नीति और कैरिंग कैपेसिटी अध्ययन पर फोकस

पथ प्रवाह, देहरादून

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के क्रम में उत्तराखण्ड में आवास एवं शहरी विकास से जुड़ी योजनाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं समयबद्ध ढंग से लागू करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सचिव-आवास, राज्य संपत्ति तथा आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के आयुक्त एवं मुख्य प्रशासक डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में यूएचयूडीए से संबंधित योजनाओं की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक सचिव आवास के कॉन्फ्रेंस कक्ष में आयोजित की गई।

यूएचयूडीए की संरचना व कार्यों का विस्तृत प्रस्तुतीकरण

बैठक के दौरान कार्यक्रम प्रबंधक, यूएचयूडीए ने प्राधिकरण की स्थापना, संगठनात्मक संरचना, विधिक प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित कार्यों, विशेष नीतियों, नियमों एवं संशोधनों पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। इसमें ॥ष्ठ तथा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों के गठन, वर्ष 1973 के अधिनियम के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों एवं अवस्थापना विकास परियोजनाओं की जानकारी साझा की गई।

प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना

(शहरी) 1.0 एवं 2.0 की प्रगति पर विशेष फोकस किया गया। सचिव आवास ने निर्माण, स्वीकृति एवं आवंटन की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किए जाएं, ताकि शहरी क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों को समय पर आवास उपलब्ध कराया जा सके।

नई आवास नीति तैयार करने के निर्देश

सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि वर्ष 2017 में जारी उत्तराखण्ड आवास नीति की वैधता समाप्त हो चुकी है, ऐसे में राज्य के लिए एक नई आवास नीति तैयार किया जाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि नई नीति में शहरीकरण की वर्तमान चुनौतियों, किफायती आवास, पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों तथा सतत विकास को विशेष रूप से शामिल किया जाए।

एमडीडीए और एचआरडीए परियोजनाओं पर जोर

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 की समीक्षा के दौरान देहरादून-मसूरी विकास प्राधिकरण की परियोजनाओं में लॉटिंग एवं आवंटन की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। वहीं हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण द्वारा लंबित विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने पर बल दिया गया।

सितम्बर 2026 तक पीएमएवाई 1.0 पूर्ण करने के निर्देश

एनपीएमसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 से संबंधित सभी कार्यों को निर्धारित समय-सीमा सितम्बर 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। सचिव आवास ने 15 दिनों के भीतर आवंटन सहित सभी औपचारिक प्रक्रियाएं पूर्ण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को पत्र निर्गत करने को कहा।

कैरिंग कैपेसिटी असेसमेंट स्टडी पर विशेष चर्चा

बैठक में कैरिंग कैपेसिटी असेसमेंट स्टडी के लिए तैयार ड्राफ्ट ऋऋक्कपर भी विस्तृत चर्चा हुई। सचिव आवास ने इसे राज्य के प्रमुख नगरों, तीर्थस्थलों, विशेष रूप से चारधाम क्षेत्रों एवं अन्य संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए इसे प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने के निर्देश दिए, ताकि विकास कार्य पर्यावरणीय संतुलन के अनुरूप किए जा सकें।

आगामी बैठकों के लिए रोडमैप तय

सचिव आवास ने निर्देश दिए कि आगामी बैठक में पीएमयू टीम का परिचय, पीएमएवाई (शहरी) 1.0 एवं 2.0 की प्रगति, शासन को प्रस्तुत विभिन्न ड्राफ्ट नीतियों एवं ड्राफ्ट ऋऋक्कपर की विस्तृत समीक्षा की जाए। साथ ही ॥ष्ठ से संबंधित सभी नियम, विनियम, उपविधियां एवं नीतियों की प्रतियां संदर्भ हेतु उपलब्ध कराने को कहा गया।

वरिष्ठ अधिकारियों की रही मौजूदगी

बैठक में संयुक्त मुख्य प्रशासक ॥ष्ठ, पीएमयू टीम, विशेष सचिव आवास एवं शहरी विकास, निदेशक/उप सचिव आवास रजनीश जैन, अपर सचिव राहुल सुन्द्रीयाल, संयुक्त मुख्य प्रशासक दिनेश प्रताप सिंह, कार्यक्रम प्रबंधक कैलाश चन्द्र पांडेय, हाउसिंग विशेषज्ञ रोहित रंजन, संस्थागत सुधार विशेषज्ञ कामना करण तथा आईटी व एमआईएस विशेषज्ञ सचिन नौटियाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

सचिव आवास का बयान

डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि आवास एवं शहरी विकास से जुड़ी सभी योजनाओं को पारदर्शी, समयबद्ध एवं जनहितैषी तरीके से लागू किया जाए।

नई आवास नीति, प्रधानमंत्री आवास योजना की नियमित समीक्षा तथा कैरिंग कैपेसिटी अध्ययन के माध्यम से राज्य में संतुलित, पर्यावरण-संवेदनशील और सतत विकास को मजबूती प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में जनसेवा का नया रिकॉर्ड, 484 कैम्पों से 3.89 लाख लाभान्वित

पथ प्रवाह, देहरादून

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने जनकल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए चलाए जा रहे 'जन-जन की सरकार जन-जन के द्वार' के तहत आयोजित विशेष कैम्पों को जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है। राज्य सरकार की प्रभावी कार्ययोजना और प्रशासनिक सक्रियता का ही परिणाम है कि बड़ी संख्या में आम नागरिक इन कैम्पों के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं।

आज आयोजित किए गए कुल 10 कैम्पों में 12,510 व्यक्तियों ने सहभागिता की, जो सरकार की जनहितकारी नीतियों पर आम जनता के विश्वास को दर्शाता है। वहीं, अब तक की कुल अवधि में राज्यभर में 484 कैम्पों का आयोजन किया जा चुका है, जिनके माध्यम से कुल 3,89,868 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से

सेवाओं का लाभ प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना है। इसके लिए प्रशासन को जनता के द्वार तक ले जाने की नीति पर कार्य किया जा रहा है। ये कैम्प शासन और जनता के बीच सेतु का कार्य कर रहे हैं तथा त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी सेवा वितरण सुनिश्चित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि वे इसी प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए अधिक से अधिक लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाएँ। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में ये प्रयास राज्य के समग्र विकास में मील का पत्थर साबित होंगे।

एक नजर

मान सरकार को स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से कड़ी फटकार

अमृतसर। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कड़ी फटकार लगा दी है। मालेरकोटला जिला अस्पताल में आई.सी.यू. की अनुपस्थिति को अदालत ने 'हैरान करने वाला और चौंकाने वाला' बताकर गंभीर चिंता जाहिर की है। चीफ जस्टिस शील नागू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव को निर्देश दिया कि वे पंजाब के सभी जिला अस्पतालों में आई.सी.यू. सुविधाओं की स्थिति पर विस्तृत शपथ पत्र दाखिल करें। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मामला केवल मालेरकोटला तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राज्य के सभी जिलों के सिविल अस्पतालों में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की जाएगी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि मालेरकोटला जिला अस्पताल, जो आसपास के कई क्षेत्रों के लिए रेफरल अस्पताल है, वहां आज तक आई.सी.यू. की सुविधा उपलब्ध नहीं है। हाईकोर्ट ने इस मुद्दे को और व्यापक बनाकर सवाल भी उठाया कि प्रत्येक जिला अस्पताल में सी.टी.स्कैन और एम.आर.आई. मशीनें अनिवार्य क्यों नहीं हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का हवाला देकर अदालत ने कहा कि पंजाब के 23 जिलों में से केवल 6 जिलों में ही एम.आर.आई. मशीनें उपलब्ध हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को दिखाता है। यह मामला भीष्म किंगर द्वारा दायर जनहित याचिका से जुड़ा है, जिसमें इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने सी.टी. स्कैन और एम.आर.आई. सेवाओं को निजी लैब्स को आउटसोर्स करने पर भी सवाल उठाकर कहा कि जनता को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना राज्य की जिम्मेदारी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जिला और उप-मंडल स्तर के अस्पतालों में ये सुविधाएं आज के समय में अनिवार्य हैं।

यासीन मलिक से जुड़ी एनआईए की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय, कोई तत्काल सुनवाई की जरुरत नहीं

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की उस याचिका पर सुनवाई की कोई तत्काल जरुरत नहीं है, जिसमें जम्मू और कश्मीर मुक्ति मोर्चा (जेकेएलएफ) के प्रमुख और अलगाववादी नेता यासीन मलिक के लिए आतंकवाद वित्तपोषण मामले में मृत्युदंड की मांग की गई है, क्योंकि यासीन आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं और इस याचिका में केवल सजा बढ़ाने की मांग की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एनआईए को यासीन मलिक के जवाब पर प्रतिउत्तर दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया। न्यायमूर्ति नवीन चावला और रविंदर दुदेजा की पीठ ने एनआईए वकील अक्षय मलिक और खावर सलीम के अनुरोध पर अतिरिक्त समय दिया। अक्षय मलिक ने बताया कि मलिक ने सितंबर में एजेंसी की याचिका के जवाब में 70 पृष्ठों का उत्तर दाखिल किया था और एजेंसी को जवाब देने के लिए और अधिक समय चाहिए।

यासीन मलिक, जो ऑनलाइन पेश हुए, ने अनुरोध का विरोध किया। उन्होंने कहा कि एजेंसी ने 10 नवंबर को पिछली सुनवाई के दौरान अपना जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था। मलिक ने कहा कि वह तीन साल से मृत्युदंड को लेकर अनिश्चितता में हैं, जो उनके लिए एक तरह का आघात है। एनआईए के वकील ने तर्क का खंडन कर कहा कि मलिक को अपना जवाब दाखिल करने में एक साल लगा और एजेंसी केवल दो से तीन सप्ताह का समय मांग रही है, क्योंकि प्रतिवाद समीक्षा के लिए भेजा गया है। चूंकि यासीन आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं है। एजेंसी केवल सजा में वृद्धि चाहती है, इसीलिए एजेंसी को अपना जवाब दाखिल करने दें। पीठ ने अगली सुनवाई की तारीख 22 अप्रैल तय की।

मई 2022 में निचली अदालत ने मलिक को सख्त गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी मानकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने 2017 में कश्मीर में आतंकी वित्तपोषण, आतंकवाद फैलाने और अलगाववादी गतिविधियों से संबंधित आरोपों में दोषी होने की बात स्वीकार की थी।

मणिपुर में राहत कार्यों की निगरानी जारी, सुप्रीम कोर्ट ने जजों की समिति का कार्यकाल बढ़ाया

नई दिल्ली,(ईएमएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में जारी जातीय हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की निगरानी कर रही सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की समिति का कार्यकाल 31 जुलाई, 2026 तक बढ़ाया है। यह निर्णय मई 2023 से राज्य में जारी मानवीय संकट को देखकर लिया गया है, जहां जनजातीय कुकी और बहुसंख्यक मैतेई समुदाय के बीच हिंसा में बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं।

सीजेआई न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखकर समिति का कार्य जारी रहना जरुरी है। अदालत ने समिति से यह भी अनुरोध किया कि वह निर्धारित अवधि के भीतर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का हर संभव प्रयास करे। समिति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि समिति अब तक अपना पूरा कार्य नहीं कर सकी है और इस कारण समय-सीमा में विस्तार की आवश्यकता है। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरामानी भी उपस्थित थे। अदालत को बताया गया कि समिति अब तक 32 रिपोर्टें प्रस्तुत कर चुकी है, जबकि कई रिपोर्टें अभी प्रक्रियाधीन हैं। जुलाई 2025 के बाद समिति को कोई औपचारिक विस्तार नहीं दिया गया था।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2023 में मणिपुर में मानवीय सहायता और पुनर्वास प्रयासों की निगरानी के लिए इस समिति का गठन किया था। यह एक पूर्णतः महिला समिति है, जिसमें जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल, बॉम्बे उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति शालिनी पी. जोशी और दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशा मेनन शामिल हैं। समिति को महिलाओं के खिलाफ हिंसा, राहत शिविरों में रह रहे लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, मुआवजे के भुगतान, चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता, धार्मिक स्थलों की बहाली और पीड़ितों के सम्मानजनक पुनर्वास जैसे अहम मुद्दों की जांच का दायित्व सौंपा गया है। पिछले दो वर्षों में समिति की रिपोर्टों ने मणिपुर में जारी मानवीय संकट के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर किया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से तीन किलोमीटर की सड़क ने दो गांवों को जोड़ा

पथ प्रवाह, अल्मोड़ा।

ग्रामीण कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने की दिशा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक प्रभावी माध्यम बनकर सामने आ रही है। इसी क्रम में जनपद अल्मोड़ा के विकासखंड सल्ट अंतर्गत ग्राम मनालधूरा से नाननकोटी तक 3 किलोमीटर लंबे मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिससे क्षेत्र के ग्रामीणों को आवागमन की बेहतर सुविधा उपलब्ध हुई है।

इस मोटर मार्ग के निर्माण से दोनों गांवों के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार एवं प्रशासनिक सेवाओं तक पहुंचने में अब किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है। पूर्व में ग्रामीणों को लगभग 10 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी पड़ती थी, जिससे विशेषकर बुजुर्गों, महिलाओं और विद्यार्थियों को भारी परेशानी होती थी।

अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई सल्ट आशीष कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि करीब 3 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह सड़क ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि योजना का उद्देश्य दूरस्थ गांवों को बारहमासी सड़क सुविधा उपलब्ध कराकर सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देना है। इस परियोजना से 391 ग्रामीणों को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुआ है। सड़क बनने से कृषि उत्पादों एवं स्थानीय वस्तुओं के परिवहन में आसानी हुई है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिला है। साथ ही, आपात स्थितियों में एम्बुलेंस एवं अन्य आवश्यक सेवाओं की पहुंच भी अब सुनिश्चित हो सकी है।

स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन एवं संबंधित विभाग का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सड़क निर्माण से क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएं खुली हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह मार्ग न केवल उनके जीवन को आसान बनाएगा, बल्कि आने वाले समय में क्षेत्र के समग्र विकास में भी सहायक सिद्ध होगा।

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन पर संत समाज में शोक की लहर

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

बुधवार सवेरे बारामती में हुई विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री तथा नेशनल कांग्रेस पार्टी के संस्थापक अजीत पवार के निधन से जहां पूरा देश गहरे सदमे में है वहीं संत समाज तथा समस्त अखाड़ों में भी शोक की लहर दौड़ गई है। पंचदश नाम जूना अखाड़े के अंतरराष्ट्रीय संरक्षक तथा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री महंत हरि गिरी महाराज ने उनके आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनके इस आकस्मिक निधन से जहां राष्ट्र को अपूरणीय क्षति हुई है वही देश की राजनीति में एक शून्य व्याप्त हो गया है जिसकी भरपाई करना असंभव है। उन्होंने कहा अजीत पवार अत्यंत दूरदर्शी मेधावी तथा कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में पूरे देश में अपना विशिष्ट स्थान रखते थे। उनका साधु संतों से विशेष स्नेह था। कुंभ मेला नासिक में होने वाले महाकुंभ 2027 में की समस्त व्यवस्थाओं को वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर देख रहे थे। उनके निधन से कुंभ मेले की तैयारी में भी व्यवधान आया है। महंत हरि गिरी महाराज के निर्देश पर अखाड़े के सभी प्रमुख मठों, हनुमान घाट वाराणसी ,मौज गिरी मंदिर प्रयागराज, भावनाथ मंदिर गुजरात, दातार अखाड़ा नीलगंगा उज्जैन ,नील पर्वत दत्तात्रेय मंदिर नासिक सहित सभी स्थानों पर विशेष शांति पाठ तथा श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जा रही है। हरिद्वार में पौराणिक सिद्ध पीठ मायादेवी मंदिर तथा आनंद भैरव मंदिर स्थित भैरव घाट पर अखाड़े के अंतरराष्ट्रीय महामंत्री श्री महंत महेश पुरी महाराज के साथ साधु संतों नागा संन्यासियों ने मां गंगा, भगवान दत्तात्रेय, महामाया देवी से उनकी आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना की तथा शांति पाठ का आयोजन किया। इस मौके पर महंत पशुपति गिरी, महंत भीष्म गिरी ,महंत भास्कर पुरी ,महंत आदित्य गिरी, महंत ग्वाला पुरी, महंत आकाश गिरी, महंत अमृत पुरी, महंत रणधीर गिरी सहित कई लोग उपस्थित थे।

एसपी उत्तरकाशी ने गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का किया निरीक्षण, बर्फबारी में सैलानियों की सुरक्षा को लेकर निर्देश

पथ प्रवाह, उत्तरकाशी।

जनपद उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले पर्यटन स्थलों पर हो रही बर्फबारी से खरसाली (खुशीमठ), जानकीचट्टी, मोरी, सांकरी, हरकीदून, राडीटॉप, चौरंगी, सुक्कीटॉप और हर्षिल घाटी जैसे क्षेत्र सैलानियों से गुलजार हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेने इन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में सैलानियों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी कमलेश उपाध्याय ने 28 जनवरी 2026 को उत्तरकाशी से हर्षिल तक गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसपी ने पुलिस विभाग तथा पर्यटन रूट से जुड़ी अन्य एजेंसियों के अधिकारियों और कर्मचारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने बर्फबारी से अवरुद्ध मार्गों पर शीघ्र बर्फ हटाने, चुनें का छिड़काव करने तथा आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाकर मार्ग को तुरंत सुचारु करने के निर्देश दिए। मार्ग पर तैनात पुलिस कर्मियों को पर्यटकों की हरसंभव सहायता करने, यातायात व्यवस्था को स्मूथ बनाए रखने और मौसम खराब होने या मार्ग अवरुद्ध होने की स्थिति में पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने के निर्देश भी दिए गए। आवश्यकता पड़ने पर अलाव की व्यवस्था करने पर भी जोर दिया गया। एसपी ने संवेदनशील और दुर्घटना संभावित स्थलों व मोड़ों पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने तथा यातायात संकेत बोर्डों को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। साथ ही पर्यटकों से फीडबैक लेते हुए अपील की कि बर्फबारी वाले क्षेत्रों में वाहन धीमी गति से चलाएं, अतिरिक्त स्टेपनी व टूलकिट साथ रखें और पर्याप्त गर्म व ऊनी वस्त्र लेकर चलें। उन्होंने बताया कि बर्फबारी के मौसम में सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पुलिस बल तैनात है। किसी भी सहायता के लिए नजदीकी पुलिस कर्मी या डायल 112 से संपर्क किया जा सकता है। निरीक्षण के दौरान पुलिस उपाधीक्षक उत्तरकाशी जनक सिंह पंवार, प्रभारी निरीक्षक मनेरी प्रदीप तोमर, प्रभारी चौकी भटवाड़ी निखिल देव चौधरी, उपनिरीक्षक यातायात लक्ष्मण सिंह चुफाल, सहायक उपनिरीक्षक सुनील तोमर सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।

सूबे में 643 नई बहुउद्देश्यीय पैक्स समितियों का गठनः डॉ धन सिंह रावत

पथ प्रवाह, देहरादून

सूबे के सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने शासकीय आवास पर सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने प्रदेश में 643 नई बहुउद्देश्यीय पैक्स समितियों का गठन, सहकारी क्षेत्र में अनाज भंडारण योजना, तीन नई राष्ट्रीय सहकारी समितियों, एनसीईआरटी की गतिविधियों में राज्य की भागीदारी, तथा फरवरी माह में गुजरात में प्रस्तावित सहकारिता सम्मेलन की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की।

कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि गुजरात में प्रस्तावित सहकारिता सम्मेलन के सभी कार्य बिंदुओं पर समयबद्ध ढंग से तैयारियाँ पूर्ण की जाएँ। उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र को पारदर्शी, सुदृढ़ एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में सचिव सहकारिता डॉ. इकबाल अहमद ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत 643 नई पैक्स के गठन का प्रस्ताव है, जिसके सापेक्ष 621 पैक्स का गठन पूर्ण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि निबंधक कार्यालय के निर्माण के संबंध में शीघ्र ही चिन्हित भूमि पर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिला सहकारी बैंकों में वर्ग-एक, वर्ग-दो एवं वर्ग-तीन के कुल 177 रिक्त पदों पर आईबीपीएस के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया संपादित की जाएगी।

सचिव सहकारिता ने यह भी बताया कि शीघ्र ही कैडर नियमावली में संशोधन करते हुए 350 प्रोफेशनल सचिवों की नियुक्ति की जाएगी। वहीं सहकारी समिति अधिनियम-2003 एवं नियमावली-2004 में आवश्यक संशोधन कर सहकारी समितियों को और अधिक पारदर्शी एवं सशक्त बनाया जाएगा।

निबंधक सहकारिता डॉ मेहरबान सिंह बिष्ट ने विभागीय प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि सहकारी संस्थाओं के डिजिटलीकरण, मानव संसाधन सुदृढ़ीकरण एवं शासन स्तर पर सुधारात्मक कदमों से सहकारिता आंदोलन को नई दिशा मिल रही है और भंडारण योजना के अंतर्गत जनपद हरिद्वार की चार पैक्स में 1000 मेट्रिक टन के गोदाम हेतु भूमिका चयन व इसकी डीपीआर तैयार कर ली गई है राज्य की भौगोलिक स्थिति की दृष्टिगत राज्य में समस्त जनपदों में 95 विकास करो में रिक्त पड़ी भूमि पर न्यूनतम 50 से लेकर 500 मेट्रिक टन के कुल 95 गोदाम बनाए जाने की कार्यवाही गतिमान है। तीन बहु राज्य सहकारी समितियां के गठन के तहत एन सी ओ एल नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट समिति भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड के साथ समझौता किया जाना है। राज्यों में सहकारिता कानून में वर्तमान समय अनुसार अपेक्षित बदलाव की आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया गया है कमेटी द्वारा प्रेषित सुझाव संस्कृतियों का संकलन कर शासन को अनुमोदन हेतु पत्र प्रेषित किया गया है

कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि वे दो सप्ताह बाद पुनः सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें गुजरात सम्मेलन से संबंधित सभी तैयारियाँ एवं आवश्यक पत्रावलियाँ पूर्ण कर ली जाएँ।

बैठक में सचिव सहकारिता डॉ इकबाल अहमद निबंधक सहकारिता डॉ मेहरबान सिंह बिष्ट अनु सचिव सुरेंद्र दत्त बेलवाल अपर निबंधक श्रीमती ईरा उप्रेती आनंद शुक्ल, संयुक्त निबंधक एमपी त्रिपाठी, उप निबंधक रमिंद्री मंदरवाल,सहायक निबंधक राजेश चौहान उपस्थित रहे।

प्रांतीय नगर उद्योग व्यापार मंडल से संबद्ध तहसील व्यापार मंडल का शपथ ग्रहण समारोह

पथ प्रवाह, हरिद्वार

प्रांतीय नगर उद्योग व्यापार मंडल से संबद्ध तहसील व्यापार मंडल का शपथ ग्रहण समारोह एवं व्यापारिक सम्मेलन व सम्मान समारोह गौतम फार्म हाउस में भव्य रूप से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथी श्री गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने नव निर्वाचित तहसील अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक, महामंत्री आदेश मारवाड़ी एवं सुमित चौधरी, कोषाध्यक्ष मनोज सिरोही, उपाध्यक्ष उदयराम सेमवाल, महेश सूर्यवंशी, भोला शर्मा, नितिन शर्मा, नितिन शर्मा एवं मनीष रस्तोगी, तहसील सचिव कपिल गिरी, संचित ग्रोवर, महादेव शंकर, तरुण जोशी, बलवीर रावत, विपिन शर्मा, मंगल सिंह, कमल खड़का एवं अमित शर्मा, प्रचार मंत्री अभिषेक गिरी, संयुक्त प्रचार मंत्री शिवकुमार राजपूत एवं राकेश कुमार को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। अवधूत मंडल आश्रम के परमाध्यक्ष महामंडलेश्वर संतोषानंद देव महाराज ने पूरी कार्यकारिणी को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में नगर विधायक मदन कौशिक एवं रानीपुर विधायक आदेश चौहान भी मुख्य अतिथी के तौर पर शामिल हुए और नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दीं। श्री गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने कहा कि व्यापार मंडल समाज और व्यापारियों के हितों की सशक्त आवाज है। नई कार्यकारिणी व्यापारियों की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ उठाकर संगठन को और मजबूत बनाएगी। विधायक मदन कौशिक एवं आदेश चौहान ने कहा कि व्यापार मंडल समाज की आर्थिक रीढ़ है और जनप्रतिनिधि हमेशा व्यापारियों के साथ खड़े रहेंगे। पूर्व दर्जाधारी संजय पालीवाल ने कहा कि तहसील व्यापार मंडल कार्यकारिणी जमीनी स्तर पर व्यापारियों के अधिकारों के लिए मजबूती से कार्य करेगी। संगठन की एकजुटता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। तहसील अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने कहा कि व्यापारियों के विश्वास पर पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करेंगे और सभी पदाधिकारियों को साथ लेकर संगठन को नई दिशा देंगे। प्रांतीय नगर उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष विशाल गर्ग एवं सुभाष कश्यप ने कहा कि ज्वालापुर इकाई की नई कार्यकारिणी संगठन को मजबूती देगी और व्यापारी हितों को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि संगठन में पहली बार महिला शक्ति को भी दायित्व दिए गए हैं। जल्द ही पूरे जिले में संगठन का विस्तार किया जाएगा। इस अवसर पर प्रांतीय नगर उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवकुमार कश्यप, प्रदेश सचिव मयंक मूर्ति भट्ट, शहर अध्यक्ष प्रवीण शर्मा, शहर महामंत्री विमल सक्सेना, जिला महामंत्री अश्विनी शर्मा, योगेश भारद्वाज, पूर्व मेयर प्रतिनिधि अशोक शर्मा, मनोज झा, वैध एमआर शर्मा, प्रवीण सिंघल, पंडित पवन कृष्ण शास्त्री, जगदीशलाल पाहवा, किशन बजाज सहित बड़ी संख्या में व्यापारी व गणमान्य लोग मौजूद रहे।

मोदी ने देश के विमानन क्षेत्र में अवसरों का लाभ उठाने के लिए वैश्विक निवेशकों को किया आमंत्रित

हैदराबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नागर विमान क्षेत्र में हो रहे ऐतिहासिक बदलाव और अवसरों को रेखांकित करते हुए विश्व भर के निवेशकों को इनका लाभ उठाने के लिए दीर्घकालिक दृष्टि से देश में कारोबार के लिए आमंत्रित किया है। मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये यहां विमानन उद्योग के सम्मेलन 'विंग्स इंडिया 2026' को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में, देश के एविएशन सेक्टर में एक ऐतिहासिक बदलाव आया है और यह तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन बाजार बन गया है। यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ी है और देश की विमान सेवा कंपनियां अपने बेड़े का विस्तार कर रही हैं, उन्होंने हाल के वर्षों में 1,500 से अधिक विमानों के लिए ऑर्डर दिये हैं।

उन्होंने कहा कि भारत इस समय उड्डयन क्षेत्र में कई सुधार कर रहा है जिससे देश दक्षिण के देशों और दुनिया के बीच नागर विमानन क्षेत्र के एक प्रमुख प्रवेश द्वार के रूप में उभर रहा है। यह विमानन उद्योग से जुड़े निवेशकों और विनिर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। भारत को भविष्य का प्रमुख और प्रतिस्पर्धी ट्रांस-शिपमेंट हब बताते हुए उन्होंने निवेशकों से वेयरहाउसिंग, फ्रेट फॉरवर्डिंग, एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स के क्षेत्र में अवसरों का पता लगाने का आग्रह किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया में बहुत कम देशों के पास इस क्षेत्र में भारत जैसे बड़े पैमाने पर कारोबार के अवसर, नीतिगत स्थिरता और प्रौद्योगिकी उन्नयन की महत्वाकांक्षा है। इसमें इस क्षेत्र की हर अग्रणी कंपनी और हर नवप्रवर्तक के लिए सुनहरे अवसर हैं।

उन्होंने कहा कि उड्डयन उद्योग का अगला दौर उम्मीदों से भरा है और भारत एक प्रमुख बाजार के रूप में उभर रहा है। उन्होंने देश में विमान निर्माण, पायलट ट्रेनिंग, एडवांस्ड एयर मोबिलिटी और विमान लीजिंग के बड़े अवसरों को रेखांकित करते हुए कहा कि इससे सभी हितधारकों के लिए 'विंग्स इंडिया' का महत्व और भी विशेष हो जाता है ।

उन्होंने कहा कि भारत के उड्डयन क्षेत्र की वृद्धि सरकार की दीर्घकालिक सोच का नतीजा है, जिसने हर नागरिक को आसानी से हवाई यात्रा करने में सक्षम बनाने के मिशन के साथ हवाई यात्रा को सभी के लिए सुलभ बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार क्षेत्रीय और किफायती हवाई कनेक्टिविटी और देश भर में सी-प्लेन संचालन का विस्तार करने के लिए उड़ान योजना के अगले चरण पर काम कर रही है।

उन्होंने जोर दिया कि टियर-2 और टियर-3 शहरों को हवाई अड्डों से जोड़ा गया है, और बताया कि साल 2014 में देश में 70 हवाई अड्डे थे, जबकि आज यह संख्या 160 से अधिक हो गई है। इसका मतलब है कि देश ने सिर्फ एक दशक में दोगुने से ज्यादा हवाई अड्डे बनाये हैं।

मोदी ने कहा कि 100 से अधिक हवाई अड्डों को चालू किया गया है और इसके साथ ही, सरकार ने किफायती किराया देने के लिए 'उड़ान' योजना शुरू की इससे ऐसे मार्गों पर 1.5 करोड़ लोग यात्रा कर चुके हैं, जिनमें से कई रूट पहले मौजूद भी नहीं थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने घरेलू स्तर पर सैन्य और परिवहन विमानों का उत्पादन शुरू कर दिया है और नागरिक विमान निर्माण में भी आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अपने उड्डयन क्षेत्र की जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भरता कम करना और आत्मनिर्भरता के रास्ते को मजबूत करना जरूरी है, जिससे देश में निवेश करने वाली कंपनियों को भी फायदा होगा।

उन्होंने जोर दिया कि भारत विमान डिजाइन, निर्माण और विमान एमआरओ इकोसिस्टम पर जोर दे रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत पहले से ही विमान के पुर्जों का एक प्रमुख निर्माता और आपूर्तिकर्ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने घरेलू स्तर पर सैन्य और परिवहन विमान बनाने शुरू कर दिये हैं और यात्री विमानों के विनिर्माण के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भौगोलिक स्थित, बेजोड़ घरेलू फीडर नेटवर्क और लम्बी दूरी की उड़ानों के लिए सक्षम विमान बेड़े के दम पर भारत विमानन में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब भारत में डिजाइन किये गये और विनिर्मित इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग एयरक्राफ्ट एविएशन सेक्टर को एक नयी दिशा देंगे, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जायेगा।

उन्होंने कहा कि भारत हरित विमान ईंधन पर बड़े पैमाने पर काम कर रहा है और आने वाले वर्षों में हरित विमान ईंधन का एक बड़ा उत्पादक और निर्यातक बनने के लिए तैयार है।

मोदी ने वैश्विक निवेशकों से भारत की विकास यात्रा में दीर्घकालिक सहभागी बनने और इसके माध्यम से वैश्विक उड्डयन क्षेत्र के विकास में योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने निवेशकों से इस क्षेत्र में भारत की उड़ान में 'को-पायलट' के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हुए और 'विंग्स इंडिया' की सफलता की कामना की।

नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू ने आज सुबह विंग्स इंडिया का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि 'विंग्स इंडिया 2026' में शीर्ष वैश्विक उद्योगों के प्रतिनिधि, नवाचारी और सभी हितधारक एक मंच पर आये हैं। अगले चार दिन में इस आयोजन में देश की बढ़ती क्षमता, अत्याधुनिक नवाचार और बढ़ती वैश्विक भागीदारी की झलक दिखेगी जो दुनिया का विमानन केंद्र बनने की हमारी यात्रा को मजबूती प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विमानन क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास गाथा दुनिया के समक्ष पेश कर रहा है।

विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम से गांवों तक पहुंचेगी रोजगार की गारंटी

पथ प्रवाह, नई टिहरी।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) देहरादून के तत्वावधान में बुधवार को जिला कार्यालय सभागार, नई टिहरी में विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन विषय पर मीडिया कार्यशाला 'वार्तालाप' का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य योजना के प्रावधानों एवं लाभों की जानकारी मीडिया के माध्यम से आम जनमानस तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना रहा।

कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य अतिथि टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल नितिका खंडेलवाल, सहायक निदेशक पीआईबी संजीव सुंद्रियाल, जिला विकास अधिकारी मोहम्मद असलम, अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई अविनाश सैनी सहित जनपद

के अनेक वरिष्ठ पत्रकार एवं मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

मुख्य अतिथि किशोर उपाध्याय ने कहा कि विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को रोजगार और आय सुरक्षा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा कि इस मिशन के अंतर्गत रोजगार सृजन के साथ-साथ टिकाऊ ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण पर विशेष बल दिया गया है। जल सुरक्षा, ग्रामीण सड़कें, आजीविका आधारित परिसंपत्तियां, डिजिटल कनेक्टिविटी और जलवायु परिवर्तन से निपटने वाले कार्य गांवों को आत्मनिर्भर बनाएंगे।

जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने कहा कि मनरेगा के नए स्वरूप में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन को लागू करते समय आने वाली व्यवहारिक समस्याओं को शासन स्तर पर प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध लाभ मिल सके। उन्होंने मीडिया से योजनाओं के सकारात्मक और तथ्यपरक प्रचार में सहयोग का आह्वान किया।

सहायक निदेशक पीआईबी संजीव सुंद्रियाल ने बताया कि अधिनियम के तहत प्रति ग्रामीण परिवार रोजगार गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। यह मिशन चार प्राथमिकता क्षेत्रों में मजदूरी आधारित रोजगार को टिकाऊ ग्रामीण अवसंरचना से जोड़ता है।

कार्यशाला का संचालन वरिष्ठ पत्रकार देवेन्द्र दुमोगा ने किया। मीडिया प्रतिनिधियों के साथ संवाद के माध्यम से योजनाओं से जुड़े प्रश्नों और सुझावों पर विस्तार से चर्चा की गई।

एक नजर

यूजीसी के समानता नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय करेगा सुनवाई

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के हाल ही में नोटिफाइड नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए लिस्ट करने पर सहमति जताई। ये नियम उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति-आधारित भेदभाव को रोकने के मकसद से बनाए गए हैं, लेकिन याचिकाकर्ता ने शिकायत निवारण तंत्र से सामान्य वर्ग के छात्रों को बाहर रखने पर चिंता जताई थी।जब यह याचिका मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के सामने आई तो उन्होंने कहा, 'हमें पता है कि क्या हो रहा है। सुनिश्चित करें कि कमियों को दूर किया जाए। ये नियम यूजीसी के उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए विनियम, 2026 के तहत आते हैं। इस नियम को 13 जनवरी को नोटिफाइड किया गया था और ये देश के कई उच्च शिक्षण संस्थानों पर लागू होते हैं।

इन नियमों का उद्देश्य धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान, जाति या विकलांगता के आधार पर भेदभाव को खत्म करना था। ये नियम खासकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और विकलांग व्यक्तियों के सदस्यों के होने वाले शोषण की घटनाओं को रोकने और उच्च शिक्षा में समानता और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए थे। नियमों के तहत, उच्च शिक्षण संस्थानों को वंचित समूहों के लिए नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और भेदभाव की शिकायतों की जांच करने के लिए समान अवसर केंद्र और समानता समितियों की स्थापना करना आवश्यक है। हालांकि, सर्वोच्च अदालत के समक्ष याचिका में तर्क दिया गया है कि ये नियम प्रकृति में अनुचित इसलिए हैं, क्योंकि वे सामान्य वर्ग के छात्रों को शिकायत निवारण और संस्थागत सुरक्षा तक पहुंच से वंचित करते हैं। याचिकाकर्ता ने नियमों को उनके मौजूदा स्वरूप में लागू करने पर रोक लगाने के निर्देश मांगे हैं। याचिका में भी कहा गया है कि जाति पहचान के आधार पर शिकायत निवारण तंत्र तक पहुंच से इनकार करना 'अस्वीकार्य राज्य भेदभाव' के बराबर है। याचिका में तर्क देते हुए कहा गया है कि ऐसा चयनात्मक ढांचा प्रभावी रूप से गैर-आरक्षित श्रेणियों के खिलाफ दुश्मनी को बढ़ावा देता है और समानता के मूल उद्देश्य को कमजोर करता है। उल्लेखनीय है कि नियमों की वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं और आवेदन दायर किए गए हैं।

केदारनाथ धाम में भारी हिमपात और शून्य से नीचे तापमान के बीच मुस्तैद सुरक्षा बल

देहरादून। उत्तराखण्ड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हो रही लगातार बर्फबारी के बीच बाबा केदार की नगरी 'केदारनाथ' पूरी तरह सफेद चादर से ढक चुकी है। धाम में वर्तमान में करीब तीन से चार फीट तक बर्फ जमा है और तापमान मानइस 16 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर चुका है। इसी तरह उत्तरकाशी और चमोली जनपदों में स्थित क्रमशः गंगोत्री, यमुनोत्री और बदरीनाथ में भी लगातार बर्फीली हवाएं चलने के साथ बर्फबारी समाचार लिखे जाने के समय भी जारी है। केदारनाथ में इन विषम और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और रुद्रप्रयाग पुलिस के जवान पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। वे कड़ाके की ठंड और बर्फीली हवाओं के बावजूद, जवान मंदिर परिसर और आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में निरंतर गश्त कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में 26 जनवरी के अवसर पर इन हिमवीरों ने भारी बर्फबारी के बीच तिरंगा फहराकर राष्ट्र के प्रति अपनी अटूट भक्ति का प्रदर्शन किया। मंदिर के कपाट बंद होने के बाद भी, धाम की सुरक्षा और मास्टर प्लान के तहत हो रहे सरकारी संपत्तियों की निगरानी की जिम्मेदारी ये जवान बखूबी निभा रहे हैं। मौसम विभाग द्वारा जारी 'अलर्ट' और हिमस्खलन (एवलांच) की संभावना को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने जवानों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से कहा है कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद सुरक्षा बलों का मनोबल ऊंचा है। केदारनाथ धाम में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद है।

वीरांगना तीलू रौतेली की प्रतिमा का लोकार्पण, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूडी भूषण ने किया उद्घाटन

पथ प्रवाह, कोटद्वार।

उत्तराखंड की वीर भूमि को गौरवान्वित करने वाला एक ऐतिहासिक क्षण उस समय साक्षी बना, जब नगर कोटद्वार में महान वीरांगना तीलू रौतेली जी की भव्य प्रतिमा का विधिवत लोकार्पण उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती ऋतु खण्डूडी भूषण जी के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ।

भव्य समारोह में पारंपरिक रीति-रिवाजों, वैदिक मंत्रोच्चार एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, समाजसेवी, बुद्धिजीवी वर्ग एवं नगरवासी उपस्थित रहे।

विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूडी भूषण जी ने कहा कि वीरांगना तीलू रौतेली जी नारी शौर्य, आत्मसम्मान एवं राष्ट्रभक्ति की अमर प्रतीक हैं। उनका जीवन संघर्ष, साहस और बलिदान की ऐसी प्रेरक गाथा है, जो आने वाली पीढ़ियों को सदैव मार्गदर्शन प्रदान करती रहेगी। उन्होंने कहा कि यह प्रतिमा न केवल कोटद्वार की पहचान बनेगी, बल्कि उत्तराखंड की गौरवशाली संस्कृति और इतिहास को भी

सशक्त रूप से प्रदर्शित करेगी।

कार्यक्रम में वक्ताओं ने वीरांगना तीलू रौतेली जी के अद्वितीय पराक्रम, सामाजिक योगदान एवं ऐतिहासिक भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला। साथ ही उन्हें नमन करते हुए उनके आदर्शों को आत्मसात करने का आह्वान किया गया।

नगरवासियों में इस ऐतिहासिक अवसर को लेकर विशेष उत्साह एवं गर्व देखने को मिला। तीलू रौतेली विचार मंच द्वारा द्वारा सफल कार्यक्रम के लिए समस्त अतिथियों, सहयोगी संस्थाओं, प्रशासन एवं नागरिकों का आभार व्यक्त किया गया।

इस अवसर पर महापौर शैलेंद्र रावत, मण्डल अध्यक्ष विकासदीप मित्तल, प्रेमा खंतवाल, पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी , पूर्व महापौर हेमलता नेगी , उमेश त्रिपाठी, सतीश गौड़ , विधायक प्रतिनिधि प्रमोद केष्टवाल , कमल नेगी , जितेंद्र नेगी , महेश नेगी आदि लोग उपस्थित रहे।

जी राम जी कानून का जिक्र आते ही अभिभाषण में विपक्ष ने किया हंगामा

नयी दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के अभिभाषण के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी कानून का उल्लेख आते ही कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी सदस्यों ने अपनी सीटों पर खड़े होकर इसका विरोध किया और कानून को वापस लेने की मांग करते हुए नारेबाजी की। वंदेमातरम का जिक्र आने पर विपक्ष ने सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए थोड़ा शोर शराबा किया।

श्रीमती मुर्मु ने संसद के बजट सत्र के पहले दिन जब अभिभाषण में संसद के शीतकालीन सत्र में पारित विकसित भारत जी राम जी कानून का सरकार की उपलब्धि के रूप में उल्लेख किया तो विपक्षी सदस्य एकाएक अपनी सीटों पर खड़े होकर इसका विरोध करने लगे। विपक्षी सदस्यों ने इस दौरान इसके विरोध में नारेबाजी की और विधेयक को वापस लेने की मांग करते रहे।

कुछ देर तक चले हंगामे के बीच सदन में जहां सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जी राम जी नाम का उल्लेख आते ही मेजें थपथपाकर इसका स्वागत किया वहीं विपक्षी सदस्यों ने इसके खिलाफ नारेबाजी की। विपक्षी सदस्य हंगामे के बीच जी रामजी वापस लो के नारे लगाते रहे।

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, डीएमके के टी आर बालू सहित सभी विपक्षी दलों के सदस्यों ने अपनी सीटों पर खड़े होकर जी रामजी का विरोध किया। राष्ट्रपति विपक्षी सदस्यों के व्यवधान पर ध्यान दिये बिना अपना अभिभाषण पढ़ती रहीं। बाद में उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन ने संक्षिप्त रूप में पढे अभिभाषण के दौरान सरकार की कई उपलब्धियों का जिक्र किया लेकिन जीरामजी कानून

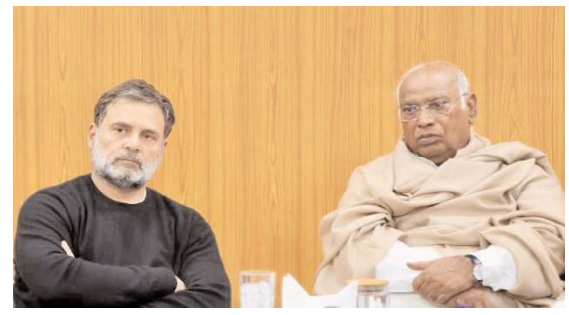

का उल्लेख नहीं किया।

अभिभाषण में जीरामजी विधेयक के उल्लेख के समय काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। सत्तापक्ष के सदस्य भी जवाब में लगातार मेजें थपथपाते रहे। श्रीमती मुर्मु जो कुछ बोल रही थीं वह हंगामे के कारण सुनाई नहीं दे रहा था लेकिन इसी बीच द्रमुक के टी आर बालू ने विपक्षी सदस्यों को शांत होने और अपनी सीटों पर बैठने का इशारा किया जिसके बाद सभी सदस्य अपनी सीटों पर बैठक गये।

विपक्षी दलों के सदस्यों ने अभिभाषण के दौरान वंदेमातरम के 150वें साल को समारोह पूर्वक मनाने का जिक्र आने के समय भी सरकार का विरोध किया। कुछ सदस्य डॉ अम्बेडकर की 15वीं जयंती पर मनाने का उल्लेख आने पर भी कुछ बोलते रहे लेकिन सुनाई कुछ नहीं दिया। वैसे हर बड़े मुद्दे पर विपक्ष की तरफ से विरोध के स्वर सुनाई दे रहे थे।

स्वामी/प्रकाशक वीरेन्द्र सिंह ने मुद्रक प्रमोद कुमार, जय माँ गंगा प्रिन्टर्स, राजराणा कॉम्पलैक्स निकट खाद गोदाम, जमालपुर कलां, ज्वालापुर, हरिद्वार (उत्तराखण्ड) से मुद्रित कराकर, मुख्य कार्यालयः 40 शांतिपुरम कॉलोनी जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार, उत्तराखंड 249408 (उत्तराखण्ड) से प्रकाशित किया। वीरेन्द्र सिंह (सम्पादक) 9411111733, डॉ सुशील शर्मा(उप संपादक) 9837906777 किसी भी वाद विवाद का निपटारा हरिद्वार में होगा। वेबसाईट- www.pathpravah.com